

43

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

तैंतालीसवीं रिपोर्ट



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

तैंतालीसवीं रिपोर्ट

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

21.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

21.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री प्रतापराव जाधव - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती सुमलता अम्बरीश
3. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
4. डॉ. निशिकांत दुबे
5. सुश्री सुनीता दुग्गल
6. श्री जयदेव गल्ला
7. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
8. डॉ. सुकान्त मजूमदार
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर
13. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
14. श्री संजय सेठ
15. श्री गणेश सिंह
16. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
17. श्री शत्रुघ्न सिन्हा
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद@
21. श्री एस. जगतरक्षकन

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी
24. डॉ. जॉन ब्रिटस
25. श्री सैयद नासिर हुसैन
26. श्री इलयराजा
27. श्री जगगेश
28. श्री प्रफुल्ल पटेल
29. श्री कार्तिकेय शर्मा
30. श्री जवाहर सरकार
31. श्री लहर सिंह सिरिया

सचिवालय

- | | | |
|---------------------------|---|--------------|
| 1. श्री सतपाल गुलाटी | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्रीमती ए. ज्योतिर्मयी | - | निदेशक |
| 3. श्री निशांत मेहरा | - | उप सचिव |

समिति का समाचार भाग - दो, दिनांक 4 अक्टूबर, 2022 का पैरा संख्या 5288 के तहत 13 सितंबर, 2022 को गठन।

प्राक्कथन

में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी यह तैतालीसवीं रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति)2022-2 (3 का गठन 13 सितंबर, 2022 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित वर्ष)2023-(24 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिन्हें 08 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 15.02.2023 को संचार मंत्रालय) दूरसंचार विभाग (के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 17 मार्च, 2023 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए, समिति उनका धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;

17 मार्च, 2023

26 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रतापराव जाधव,

सभापति,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी

संबंधी स्थायी समिति।

प्रतिवेदन

भाग-एक

I. परिचय

दूरसंचार विभाग (डीओटी) अन्य बातों के साथ-साथ दूरसंचार नीति, लाइसेंस प्रदान करने, तार, टेलीफोन, दूरसंचार वायरलेस डाटा से संबंधित मामलों का समन्वय करने; दूरसंचार से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मानक संवर्धन, दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी); और इस क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। दूरसंचार विभाग अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके रेडियो संचार के क्षेत्र में फ्रीक्वेंसी प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी है। दूरसंचार विभाग देश में सभी प्रयोक्ताओं के बेतार पारेषण पर निगरानी रखकर बेतार विनियामक उपायों को लागू करता है।

भारतीय दूरसंचार परिदृश्य

i. टेलीफोन ग्राहकों में वृद्धि:

क) कुल टेलीफोन कनेक्शन 25.42% की वृद्धि के साथ मार्च 2014 में 93.30 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 117.02 करोड़ हो गए। अक्टूबर 2022 में मोबाइल कनेक्शन की संख्या 114.4 करोड़ तक पहुंच गई। टेली-घनत्व जो मार्च 2014 में 75.23% था, अक्टूबर 2022 में 84.67% हो गया है।

ख) शहरी टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 55.52 करोड़ से 17.06% की वृद्धि के साथ बढ़कर अक्टूबर 2022 में 64.99 करोड़ हो गए, जबकि ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शनों में वृद्धि 37.69% थी, जो शहरी वृद्धि से दोगुनी है, यह मार्च 2014 में 37.78 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 52.02 करोड़ हो गई। ग्रामीण टेली-घनत्व मार्च 2014 में 44% से बढ़कर अक्टूबर 2022 में 57.91% हो गया।

ii. इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की पहुंच में वृद्धि:

क) मार्च 2014 में इंटरनेट कनेक्शन 25.15 करोड़ से बढ़कर जून 2022 में 83.69 करोड़ हो गए, जिसमें 232% की वृद्धि दर्ज की गई।

ख) ब्रॉडबैंड कनेक्शन मार्च 2014 में 6.1 करोड़ से बढ़कर सितंबर, 2022 में 81.62 करोड़ हो गए, जिसमें 1238% की वृद्धि हुई।

ग) प्रति ग्राहक प्रति जीबी वायरलेस डेटा की औसत राजस्व प्राप्ति दिसंबर 2014 के 268.97 रुपये से घटकर जून, 2022 में 10.29 रुपये हो गई, जिसमें 96.17% से अधिक की कमी आई है।

घ) प्रति वायरलेस डेटा ग्राहक औसत मासिक डेटा खपत 266 गुना बढ़कर जून, 2022 में 16.40 जीबी हो गई जो मार्च 2014 में 61.66 एमबी थी।

iii. एफटीटीएच

क) 22 अगस्त, 2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 एचएच पर एफटीटीएच ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या 15.05, शहरी क्षेत्रों में 241.20 और कुल 85.03 है।

ख) एफटीटीएच के राज्यवार आकड़े बताते हैं कि 22 अगस्त तक दिल्ली में प्रति 1000 घरों में उच्चतम एफटीटीएच (654.53) है।

iv. बीटीएस और टावर:

क) दिनांक 09.12.2022 तक मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशनों (बीटीएस) की संख्या 23.98 लाख है।

ख) 09.12.2022 तक मोबाइल टावरों की संख्या 7.4 लाख है।

II. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

2. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन 21.03.2022 को संसद में प्रस्तुत किया गया था। दूरसंचार विभाग ने बत्तीसवें प्रतिवेदन में निहित टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी कार्रवाई नोट्स 07 जून, 2022 को प्रस्तुत किया। बत्तीसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर 39वां प्रतिवेदन 9 फरवरी, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 14 सिफारिशों में से 09 सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। समिति ने 04 सिफारिशों पर टिप्पणी की थी और 01 सिफारिशों का उत्तर अंतरिम प्रकृति का पाया गया था जिस पर मंत्रालय से अंतिम उत्तर मांगे गए हैं।

उनतालीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई विवरण यथासमय संसद में रखा जाएगा।

III. दूरसंचार विभाग का बजट (2023-24)

3. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने 8 फरवरी, 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मांग संख्या 13 प्रस्तुत की। वर्ष 2019-20 से 2022-23 के लिए राजस्व और पूंजीगत खंडों के तहत वास्तविक, 2022-23 के लिए प्रस्तावित, बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक, 2023-24 के दौरान राजस्व और पूंजी के तहत प्रस्तावित और बजट अनुमान निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख शीर्ष	2019-20 वास्तविक	2020-21 वास्तविक	2021-22 वास्तविक	2022-23 प्रस्तावित	2022-23 बजट अनुमान	2022-23 संशोधित अनुमान	2022-23 वास्तविक	2023-24 प्रस्तावित	2023-24 बजट अनुमान
राजस्व खंड	26392.44	45154.71	36771.84	44843.94	32436.38	46157.80	24291.31	45244.91	41461.43
पूंजी खंड	9634.49	8356.11	6397.74	4990.97	63111.42	38745.89	33374.71	39752.07	66691.82
महा योग	36026.93	53510.82	43169.58	49834.91	95547.80	84903.69	57666.02	84996.98	108153.25

(i) राजस्व खंड

4. दिसंबर, 2022 तक राजस्व खंड के तहत व्यय का शीर्षवार विवरण निम्नवत है:

राजस्व खंड	(करोड़ रुपये में)
------------	-------------------

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	प्रमुख शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	व्यय दिसंबर, 2022 तक
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	901.30	902.37	603.82
2	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ-डीओटी	2071	19000.00	19435.56	12610.18
3	श्रम रोजगार और कौशल विकास	2230	0.42	0.42	0.00
4	वायरलेस और योजना समन्वय	3275	15.00	20.74	16.02
(क)	निगरानी सेवाएं	3275	45.00	50.31	34.12
(ग)	यूएसओएफ के लिए सेवा प्रदाताओं को मुआवजा	3275	2000.00	1380.00	826.63
(घ)	यूएसओएफ(आर एंड डी)	3275	0.00	130.00	0.00
(ङ)	रिजर्व फंड में अंतरण	3275	2000.00	1510.00	2000.00
(च)	टीडीआईपी	3275	19.00	19.00	12.76
(छ)	एमटीएनएल बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान	3275	383.57	383.57	347.95
(ज)	श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान दूरसंचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतर निधियन	3275	1.00	1.00	0.00
(झ)	4जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी अनुदान	3275	3550.00	0.00	0.00
(ञ)	बीएसएनएल और एमटीएनएल में वीआरएस का कार्यान्वयन	3275	3300.00	3300.00	2435.07
(ट)	स्वच्छता कार्य योजना के लिए विशेष सहायता	3275	2.00	1.00	0.08
(ठ)	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	3275	48.70	46.00	39.23
(ड)	सी-डॉट	3275	500.00	500.00	250.00
(ढ)	आईटीआई, बेंगलोर	3275	0.01	0.01	0.00
(ण)	ट्राई	3275	90.00	97.18	66.00
(त)	टीडीसैट	3275	19.20	17.50	11.88
(थ)	प्रशिक्षण (एनआईसीएफ और एनटीआईपीआरआईटी)	3275	30.00	14.74	6.89
(द)	चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	3275	3.50	52.86	24.44
(ध)	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3275	527.68	90.25	4.25

	योजना				
(न)	दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) की प्रचालन लागत	3275	0.00	0.60	0.00
(प)	स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड का प्रचालन और अनुरक्षण प्रभार	3275	0.00	5.11	1.99
(फ)	बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ)	3275	0.00	18127.00	5000.00
(ब)	गारंटी शुल्क की छूट बीएसएनएल/एमटीएनएल	3275	0.00	72.58	0.00
	कुल राजस्व खंड (सकल)		32436.38	46157.80	24291.31

5. चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान संशोधित अनुमान में आबंटित निधियों के उपयोग की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नलिखित लिखित उत्तर दिया है:

“राजस्व खंड के तहत दिसंबर, 2022 तक व्यय 24291.31 करोड़ रुपये था जो 15.02.2023 को बढ़कर 35059.89 करोड़ रुपये हो गया है जो आवंटित संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23 का 78.65% है। निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम स्तर पर निधियों के उपयोग की निरंतर निगरानी की जाती है।”

(ii) पूंजी खंड

6. पूंजी खंड के तहत व्यय का शीर्षवार विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	प्रमुख शीर्ष	बजट अनुमान 2022-23	संशोधित अनुमान 2022-23	दिसम्बर 22 तक का व्यय
1	आईटीआई पुनरुद्धार (इक्विटी निवेश)	4859	200.00	187.82	80.00

2	बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए पूंजी निवेश	5275	44720.00	33269.01	23873.44
3	निदेशालय एवं प्रशासन प्रमुख का कार्य भवन		0.01	0.01	0.00
4	डब्ल्यूएमओ प्रमुख कार्य भवन		11.00	8.30	0.28
5	डब्ल्यूपीसी		0.01	0.15	0.00
6	निगरानी सेवाएं		5.00	5.00	1.92
7	रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क		1961.00	1961.00	1000.00
8	सीआरआईएफ से अंतरित निधियाँ		1961.00	0.00	0.00
9	भारतनेट		7000.00	1500.00	1234.58
10	रिज़र्व फंड में अंतरण		7000.00	1500.00	1234.58
11	वायरलेस सेट और उपकरण (टीईसी)		15.00	5.12	0.11
12	संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान (एनआईसीएफ)		28.00	15.00	8.92
13	दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र		10.00	10.00	0.00
14	टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्ट)		31.80	111.25	26.86
15	केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)		13.00	13.00	13.00
16	स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड		10.00	2.63	0.00
17	ट्राई बिल्डिंग		135.60	135.60	135.60
18	बीएसएनएल को सेटलाइट गेटवे की स्थापना के लिए सहायता		0.00	0.00	0.00
19	डिजिटल इंटेलेजेंस यूनिट परियोजना		10.00	21.00	0.00
20	एमटीसीटीई		0.00	0.30	0.00
21	एसटीआर		0.00	0.70	0.00
	कुल पूंजी खंड		63111.42	38745.89	27609.29

7. 2023-24 के लिए सूचीबद्ध विभाग की प्राथमिकताओं के अनुसार और निधियों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजनाएं निम्नवत हैं:

“यूएसओएफ और रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (जिसे एनएफएस - स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क भी कहा जाता है) के तहत योजनाओं को 2023-24 में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, पीएलआई (उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन), टीडीआईपी

(प्रौद्योगिकी विकास और निवेश संवर्धन) और चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना जैसी योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

बीएसएनएल/एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना भी बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि बजट अनुमान 2023-24 के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल में पूंजी निवेश के लिए 52,937.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन योजनाओं के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभाग की योजनाओं पर संबंधित खंड में विस्तार से चर्चा की जाती है।

8. वर्ष 2023-24 के लिए निधियों के आवंटन में भारी वृद्धि के कारणों और इसके उपयोग के प्रस्तावों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:

“पूंजी शीर्ष के तहत, दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव अर्थात् वर्ष 2023-24 के लिए 39,725.07 करोड़ रुपये की तुलना में 66691.82 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बढ़ी हुई राशि बीएसएनएल को एजीआर बकाये के भुगतान के लिए है जो इसके पुनरुद्धार पैकेज का एक हिस्सा है। विभाग ने एजीआर बकाया के लिए 33,111.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव किया था। बीएसएनएल द्वारा राशि का दावा करने के बाद भुगतान किया जाएगा और वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भुगतान किए जाने की संभावना है।”

9. विभाग ने 2022-23 के दौरान योजनाओं के तहत निधियों के कम उपयोग के कारणों और निधियों के सुचारु कार्यान्वयन और इष्टतम उपयोग में विभाग द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को निम्नवत रेखांकित किया है:

“वर्ष 2022-23 के लिए 9000 करोड़ रुपये (भारतनेट के लिए 7000 करोड़ रुपये और अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये) का बजट अनुमान प्राप्त हुआ था। यूएसओएफ/डीओटी ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 7000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का प्रस्ताव किया जिसमें से एमओएफ द्वारा 3010 करोड़ रुपये का आरई आवंटित किया गया (भारतनेट के लिए 1500 करोड़ रुपये और "अन्य यूएसओएफ योजनाओं" के लिए 1380 करोड़ रुपये और "अनुसंधान और विकास" के लिए 130 करोड़ रुपये)। वर्ष 2022-23 के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। चरण-II का कार्य काफी हद तक 8 राज्यों (राज्य आधारित मॉडल के तहत लगभग 65000 ग्राम पंचायत) और बीएसएनएल (सीपीएसयू आधारित मॉडल में 23000 ग्राम पंचायत) पर निर्भर था। बीएसएनएल को अपने आंतरिक मुद्दों और वित्तीय कारणों से क्षमता संबंधी बाधकताओं का सामना करना पड़ा।

इसके अलावा बजट अनुमानवर्ष 2022-23 तैयार करते समय यह माना गया था कि पीपीपी मॉडल भारतनेट के तहत व्यय हो सकता है जिसके लिए वैश्विक निविदा दिनांक 19.07.2021 को जारी की गई थी और दिनांक 27.01.2022 को खोली गई थी। कोई रिस्पान्सिव बोली प्राप्त नहीं हुई। इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 में भारतनेट के पीपीपी मॉडल पर कोई खर्च नहीं किया गया। अन्य यूएसओएफ योजनाओं के मामले में प्रस्तावित संशोधित अनुमान वर्ष 2022-23, बजट अनुमान वर्ष 2022-23 के समान था। तथापि, अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 2000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा 1510 करोड़ रुपये (अनुसंधान और विकास के लिए 130 करोड़ रुपये सहित) आवंटित किए गए थे।”

बीएसएनएल/एमटीएनएल में पूंजी निवेश

बीएसएनएल को 26,386 करोड़ रुपये (20 एलएसए में 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए 23,373 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 3013 करोड़ रुपये) की पूंजीगत राशि जारी की गई थी। शेष 6883 करोड़ रुपये दिल्ली/मुंबई में 900 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, तीन एलएसए में 1800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम और दूरसंचार पीएसयू के पुनर्गठन और परिचालन एकीकरण के लिए है। बीएसएनएल ने इस राशि को बजट अनुमान वर्ष 2023-23 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है जिसका मुख्य कारण बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय के लिए तैयार की जाने वाली विस्तृत योजना है।

भारतीय दूरसंचार उद्योग

आईटीआई पुनरुद्धार के लिए निधियों के कम उपयोग के कारण:

कई इलेक्ट्रॉनिक घटकों और चिप्स का आयात करना पड़ता है जो विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में घटकों और चिप की कमी के कारण लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्या हैं जिससे लंबे समय तक आपूर्ति में देरी हो रही है। इस प्रकार निधि का उपयोग अनुमानों के अनुरूप नहीं रह सका। स्वदेशी 4जी प्रौद्योगिकी के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) में विलंब के कारण बीएसएनएल द्वारा पीओ जारी करने में विलंब हुआ। इसके कारण आईटीआई द्वारा अपने विक्रेताओं पर खरीद आदेशों के प्लेसमेंट में देरी हुई है, जिससे निधि का उपयोग कम हो गया है।

IV. सार्वजनिक सेवा दायित्व (यूएसओएफ)

10. संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित यूएसओएफ की स्थापना दिनांक 01.04.2002 से भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2006 में आगे संशोधित) के तहत देश के वाणिज्यिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। यह दूरसंचार विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, और इसका संचालन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक, यूएसओएफ द्वारा किया जाता है।

11. भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अनुसार लाइसेंस शुल्क में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी शामिल है जिसे दूरसंचार लाइसेंस धारकों के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5% की दर से वसूला जाता है। यूएएल के तहत एकत्रित निधियां भारत की संचित निधि में अंतरित की जाती हैं और इसकी प्रकृति अव्यपगत होती है। यूएसओएफ की आवश्यकता के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष बजटीय प्रावधान के माध्यम से इस निधि से यूएसओएफ में आउटफ्लो किया जाता है। यूएसओएफ की स्थापना के बाद अर्थात् वर्ष 2002-03 से 1,34,076.96 करोड़ रुपये यूएएल एकत्रित किया गया है। संसदीय अनुमोदनों के माध्यम से प्राप्त 69,590.89 करोड़ रुपये का अंतिम आवंटन को संबंधित वर्षों में शीर्ष 8235 जनरल एंड रिजर्व फंड-118 यूएसओ फंड में अंतरित किया गया था और इस प्रकार संबंधित वर्षों में किए गए आवंटन और यूएसओ फंड में अंतरित किए गए समग्र आवंटन का उपयोग किया गया है। दिनांक 31.12.2022 तक यूएसओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूएएल राशि में से 64,486.07 करोड़ रुपये की राशि शेष है। यूएसओएफ विभिन्न स्कीमों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यय की पूर्ति करने के लिए बजटीय प्रावधान करता है और दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय को निधियों की आवश्यकता अग्रेषित की जाती है। यूएसओएफ की अनुमानित स्कीमों के अंतर्गत वहन किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय से प्राप्त आवंटनों का उपयोग किया जाता है।

विभाग के अनुसार कई एजेंसियों की भागीदारी और विभिन्न मंजूरीयों को ध्यान में रखते हुए अवसंरचना परियोजनाओं के शुरू होने में समय लगता है, इसलिए समग्र शेष निधि

का एक बार में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए यूएसओएफ विभिन्न स्कीमों को पूरा करने के लिए अपेक्षित व्यय की पूर्ति करने के लिए बजटीय प्रावधान करता है और दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय को निधियों की आवश्यकता अग्रेषित की जाती है। यूएसओएफ की अनुमानित स्कीमों के अंतर्गत वहन किए गए व्यय को पूरा करने के लिए दूरसंचार विभाग की बजट शाखा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्रालय से प्राप्त आबंटनों का उपयोग किया जाता है।

12. यूएसओएफ की विभिन्न योजनाओं के लिए 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 के दौरान प्रस्तावित और 2022-23 के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक उपयोग की प्रस्तावित राशि निम्नवत है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	20-2019	21-2020	22-2021	23-2022	24-2023
प्रस्तावित	8350.00	8000.00	13250.00	9000	11400.00
ब.अ.	8350.00	8000.00	9000.00	9000	\$ 10400.00
सं.अ.	3000.00	7200.00	8300.00	\$ 3010	
वास्तविक	*2926.00	7200.00	8300.00	# 2067	
सं .अ .के संदर्भ में %	%100	%100	%100	%68.67	

* सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आवंटन के रूप में 3000 करोड़ रुपये (भारतनेट के लिए 2000 करोड़ रुपये और "अन्य यूएसओएफ स्कीमों" के लिए 1000 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 74 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के अनुरोध पर दूरसंचार विभाग को पुनःसमायोजित किए गए थे।

दिनांक 31.12.2022 तक वितरित की गई निधियां।

\$ अनुसंधान और विकास के तहत आवंटित वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 130 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 400 करोड़ रुपये सहित।

13. निधियों के कम उपयोग के कारणों और निधियों के उपयोग की गति को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत प्रस्तुत किया है:

“भारतनेट के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग का कारण राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत भारतनेट के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और पीपीपी निविदा में बोली प्राप्त न होना तथा कार्यों का आगे आबटित होना है।”

14. विभाग ने आगे बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान यूएसओएफ के तहत निम्नलिखित योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है:

- (i) भारतनेट- पूरे भारत में सभी 6 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान।
- (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) - राष्ट्रीय राजमार्गों सहित मेघालय और शेष पूर्वोत्तर क्षेत्र के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान।
- (iii) द्वीपसमूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना- कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन केबल बिछाना और अंडमान और निकोबार में मोबाइल कनेक्टिविटी।
- (iv) भारतनेट परियोजना के तहत वीसैट कनेक्टिविटी का उपयोग करके गृह मंत्रालय की एजेंसियों (सीएपीएफ), रक्षा मंत्रालय की एजेंसियों (सेना, बीआरओ) और अन्य एजेंसियों को प्रदान किए गए डिजिटल सेटलाइट फोन टर्मिनलों (डीएसपीटी) का पुनःप्रावधान।
- (v) हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों और आकांक्षी जिलों में सेवा से वंचित गांवों में मोबाइल सेवा स्कीम
- (vi) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवा स्कीम- चरण-I में 4जी उन्नयन और चरण-II में 4जी सेवाओं का प्रावधान।
- (vii) देश भर में कवर न किए गए गांवों की 4जी मोबाइल सेवाओं का सेचुरेशन।

इसके अलावा, विभाग ने बताया है:

“लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूएसओएफ स्कीमों की लगातार निगरानी कर रहा है, बाधाओं, यदि कोई हो, का समाधान कर रहा है, पीएमजी पोर्टल आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्राप्त करने में सहायता कर रहा है। इसके अलावा नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, डीईए आदि जैसे विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा नियमित आधार पर स्कीमों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। निधियों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुमान लागत और प्रतिबद्ध देनदारियों के उचित मूल्यांकन के बाद वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट तैयार किया गया था।”

क. भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

15. विभाग के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक, भारतनेट को देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में हाई बैंड विड्थ कैपसिटी, मोबाइल सेवाओं और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए, यूएसओएफ के वित्तपोषण से शुरू हुई योजनाओं में से एक योजना भारतनेट है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित चरण -1 और चरण -2 दोनों को मिलाकर भारतनेट का कुल वित्त पोषण 42,068 करोड़ रुपये (जीएसटी, ऑक्ट्रॉय और स्थानीय करों को छोड़कर) है। अबपरियोजना का दायरा सभी बसे हुए गांवों तक बढ़ा दिया गया है।

16. 2022-23 के दौरान प्रस्तावित, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक, 2023-24 के दौरान प्रस्तावित और बजट अनुमान के संबंध में विवरण निम्नवत है:

(रु.करोड़ में)					
वर्ष	20-2019	21-2020	22-2021	23-2022	24-2023
प्रस्तावित	6000.00	6000.00	10000.00	7000.00	6000.00
ब.अ.	6000.00	6000.00	7000.00	7000.00	5000.00
सं.अ.	*2000.00 1657.74)करोड़ रुपये के रूप में पुन : समायोजित(5500.00 5919.79)के रूप में पुन : समायोजित(7000.00 7510.96)के रूप में पुन : समायोजित(1500.00	
वास्तविक	1657.74	5919.79	7510.96	1280.00#	
संशोधित अनुमान के संदर्भ में%	%100	%100	%100	%85	

दिनांक 31.12.2022 तक व्यय।

ख. भारतनेट चरण-1 का कार्यान्वयन और स्थिति

17. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) -भारतसंचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (रेलटेल) और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी

अंतर को मिटाने के लिए इन्फ्रीमेंटल फाइबर बिछाकर और मौजूदा फाइबर का उपयोग करके हुए ब्लॉक मुख्यालयों (बीएचक्यू) से ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 25.10.2011 को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन/अब भारतनेट) के सृजन हेतु परियोजना मंजूर की थी। इस एनओएफएन के निष्पादन, प्रबंधन और प्रचालनों के लिए भारतब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को एक विशेष प्रयोजन साधन (मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के साथ बीबीएनएल के विलय को मंजूरी दी है) के रूप में दिनांक 25 फरवरी, 2012 को शामिल किया गया था। इसे भारतनेट का चरण-1 माना गया था। एक लाख ग्राम पंचायतों में कार्यान्वयन होने के साथ चरण-1 का कार्य दिसम्बर 2017 में पूरा हुआ था। इसके बाद, दिनांक 19 जुलाई, 2017 को मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार चरण-1 का दायरा 1.25 लाख ग्राम पंचायतों (संशोधित कार्य क्षेत्र चरण-1) तक बढ़ा दिया गया था।

दिनांक 09.01.2023 तक

सीपीएसयू	चरण-1 में नियोजित ग्राम पंचायतें	बिछाई गई (किलोमीटर)	ओएफसी सेवा प्रदान करने को तैयार ग्राम पंचायतें
बीएसएनएल	101767	251047	101266
रेलटेल	7991	27974	7979
पीजीसीआईएल	10396	31172	10358
बीबीएनएल/बीएसएनएल	66	213	62
कुल	1,20,220	3,10,406	1,19,665

ग. भारतनेट चरण- II:

18. मंत्रिमंडल ने दिनांक 19 जुलाई 2017 को भारतनेट के लिए एक संशोधित कार्यनीति को मंजूरी दी, जो परियोजना के चरण-1 के कार्यान्वयन अनुभव को एकीकृत करती है और इससे डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार होती दिखाई पड़ती है। संशोधित कार्यनीति ग्राम पंचायतों (जीपी) को जोड़ने के लिए मीडिया (ओएफसी/रेडियो/सैटेलाइट) का इष्टतम मिश्रण प्रदान करती है, प्रत्येक जीपी को 1 जीबीपीएस बैंडविड्थ (वायर्ड मीडिया पर) प्रदान किया जाता है, जीपी और ब्लॉक के बीच नया फाइबर बिछाया जाता है, बहु-कार्यान्वयन मॉडल-राज्य-आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र और सीपीएसयू मॉडल सहित वाई-फाई या किसी अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में अंतिम दरवाजे तक कनेक्टिविटी प्रदान करती है। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित भारतनेट (चरण-1 और चरण- II) की कुल निधि 42,068 करोड़ रुपये

(जीएसटी, चुंगी और स्थानीय करों को छोड़कर) है। चरण-I बनाम चरण-II की मुख्य विशेषताओं का तुलनात्मक चार्ट अनुबंध-I में दिया गया है।

19. विभाग से 09.01.2023 तक भारतनेट परियोजना की समग्र उपलब्धि: भारतनेट परियोजना भौतिक प्रदर्शन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर लिखित उत्तर में निम्नवत बताया गया है:

क्र. सं.	चरण	नियोजित ग्राम पंचायतें	बिछाई गई ग्राम पंचायतें ओएफसी (किमी)	जहां केबल बिछाई गई	सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतें
1.	चरण I	120220	3,10,406	1,24,502	1,19,665
2.	चरण II	102,437	3,01,822	72,727	67,624
	कुल	222,657	6,12,228	1,97,229	1,87,289
3.	भारतनेट सैचुरेशन	41978 ग्राम पंचायतें और गाँव	काम किया जा रहा है		
	कुल	264635	6,12,228	1,97,229	1,87,289

20. कार्यात्मक इंटरनेट कनेक्शन वाली ग्राम पंचायतों की स्थिति का पता लगाने के लिए तैयार किए गए तंत्र के संबंध में विभाग ने निम्नवत बताया है:

“अब तक ग्राम पंचायतों तक भारतनेट अवसंरचना के सृजन पर जोर दिया जाता था। वर्तमान में लगभग 71% ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है और अब वाई-फाई हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन, लीज लाइनों, डार्क फाइबर, बैकहॉल से मोबाइल टावरों आदि के माध्यम से ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं के प्रावधान के लिए सृजित बुनियादी ढांचे का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है।”

विभाग द्वारा की गई पहलों का वर्णन करते हुए निम्नवत बताया गया है:

- (i) बीएसएनएल/बीबीएनएल की फ्रैंचाइजियों और राजस्व हिस्सेदारी भागीदारों को जोड़ने के लिए बीएसएनएल ने फ्रैंचाइजी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित की है और 2614 से अधिक फ्रैंचाइजी बनाई गई हैं।
- (ii) भारतनेट उद्यमी स्कीम- इस स्कीम के एक भाग के रूप में, एफटीटीएच कनेक्शन वाले ब्लॉक के सैचुरेशन के लिए 4 ब्लॉकों की पहचान की गई थी, जिसमें ब्लॉक

की सभी ग्राम पंचायतों को एफटीटीएच कनेक्टिविटी के साथ 5% घरों को प्रदान करने के उद्देश्य से बीएसएनएल द्वारा जोड़ने का प्रस्ताव किया गया था। मुख्य उद्देश्य मांग मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन था जब किसी विशेष भूगोल में कतिपय प्रतिशत परिवारों को एफटीटीएच कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। प्रारंभ में 40,000 कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ दिनांक 1 अक्टूबर, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक दो महीनों के लिए पायलट लॉच किया गया था। बाद में इसे 1,00,000 कनेक्शन के लक्ष्य के साथ दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। इन ग्राम पंचायतों और आसपास के गांवों में पहले दो महीनों यानी अक्टूबर और नवंबर, 2022 में कुल 41,000+ कनेक्शन सक्रिय किए गए हैं और जनवरी, 2023 के पहले सप्ताह तक 1 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। अब, देश भर में 5 लाख कनेक्शनों के विस्तार पर विचार किया जा रहा है।

- (iii) वित्त मंत्रालय की विशेष सहायता स्कीम के तहत, भारतनेट का उपयोग करके सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों और घरों में एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 2700 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारतनेट अवसंरचना का उपयोग करते हुए एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए बीएसएनएल/अन्य आईएसपी के साथ समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे संस्थानों के लिए हाई-स्पीड डाटा कनेक्शनों की मांग पूरा करने के लिए उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों के साथ बातचीत की जा रही है।
- (v) मांग पंजीकरण पोर्टल '<https://ruralfiber.bsnl.co.in>' विकसित किया गया है और मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है।
- (vi) जीपी स्तर तक लाइव नेटवर्क की स्थिति देखने के लिए ऑनलाइन पोर्टल '<https://bharatnetlive.bbnlindia.in/UNMS/index.jsp>' विकसित किया गया है।
- (vii) 8 राज्यों में, राज्य के नेतृत्व वाले एसपीवी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य के नेतृत्व वाले एसपीवी को बीएसएनएल या किसी भी आईएसपी के साथ राजस्व साझा करने की व्यवस्था करने और सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के लिए राजी किया जा रहा है।
- (viii) भारतनेट चरण-II (सैटेलाइट मीडिया से जोड़े जा रहे) लगभग 5500 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रावधान का कार्य भी सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से वित्त पोषण के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतनेट चरण-II (ओएफसी/रेडियो पर कार्यान्वित किया जा रहा है) के लिए संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां सृजित नेटवर्क के उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।”

21. विभाग से भारतनेट जैसी महत्वपूर्ण योजना के तहत निधि के आवंटन को बजट अनुमान 2022-23 में 7,000 करोड़ रुपये से घटाकर बजट अनुमान 2023-24 में 5000 करोड़ रुपये करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया गया:

“बजट अनुमान वर्ष 2022-23 तैयार करते समय, यह माना गया था कि भारतनेट के पीपीपी मॉडल के तहत व्यय हो सकता है, जिसके लिए वैश्विक निविदा दिनांक 19.07.2021 को जारी की गई थी और दिनांक 27.01.2022 को बोली लगाई गई थी। कोई उत्तरदायी बोली प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 में भारतनेट के पीपीपी मॉडल पर कोई खर्च नहीं किया गया, भले ही वित्त वर्ष 2022-23 में इसकी उम्मीद थी। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, भारतनेट के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 2023-24 में 6000 करोड़ रुपये था, जिसके विरुद्ध वित्त मंत्रालय से 5000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित वास्तविक प्रगति पर आधारित थी। अतः, भारतनेट के अंतर्गत कम उपयोग का कारण राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के अंतर्गत भारतनेट के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति और पीपीपी निविदा में बोली प्राप्त न होना तथा कार्यों का आगे आबंटन होना है।”

घ. भारतनेट नेटवर्क का उपयोग

22. नेटवर्क के उपयोग के संबंध में, विभाग ने कहा है कि उसने बैंडविड्थ और डार्क फाइबर को पट्टे पर देने, सार्वजनिक स्थानों पर ब्रॉडबैंड/इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए वाई-फाई और स्कूलों, अस्पतालों, डाकघरों, आंगनवाड़ी, ग्राहक सेवा केंद्रों, पुलिस स्टेशन आदि जैसे सरकारी उपकरणों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) के माध्यम से उपयोग प्रस्तावित है। विवरण निम्नवत हैं:

क) सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों के माध्यम से भारतनेट नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। दिनांक 09.01.2023 तक, 5789 टीबी डेटा (दिसंबर) का उपयोग करके 1,04,664 जीपी में वाई-फाई स्थापित किया गया है और 2,18,885 फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। डार्क फाइबर की लीजिंग लगभग 58,648 किमी और बैंडविड्थ की लीजिंग 3,619 जीबीपीएस है। राज्य वाइड एरिया नेटवर्क

(एसडब्ल्यूएन) 17,014 ग्राम पंचायतों पर भारतनेट नेटवर्क का उपयोग कर रहा है।

भारतनेट फाइबर के माध्यम से 1,660 टावरों को फाइबरयुक्त किया गया है।

ख) भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करते हुए एक लाख एफटीटीएच कनेक्शनों को चालू करने के लिए बीएसएनएल के एक पायलट प्रस्ताव को यूएसओएफ द्वारा आइएलएल और पूंजी प्रोत्साहन दोनों के लिए 89 करोड़ रुपये की वित्तीय सब्सिडी के साथ अनुमोदित किया गया है। यूएसओएफ सब्सिडी में प्रति एफटीटीएच 4500/- रुपये का पूंजीगत प्रोत्साहन शामिल है और 4 लाख रु. एक वर्ष के लिए प्रति मिनी-ओएलटी प्रति 100 एमबीपीएस आइएलएल सब्सिडी है जो बीएनयू को दिया जाना है। इसके अलावा, बीएसएनएल ने परियोजना के तहत भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करते हुए 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन के लिए मंजूरी मांगी है, जिसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। दिनांक 11.01.2023 तक, पूरे देश में पायलट के तहत लगभग 1,11,196 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

23. 31.12.2022 को भारतनेट के कार्यान्वयन/उपलब्धि की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

1. उपयोग की गई निधियां: दिनांक 31.12.2022 तक 36800 करोड़ रुपये
2. बिछाई गई ओएफसी: 6,11,036 किमी
3. जोड़ी गई/ सेवा प्रदान करने के लिए तैयार जीपी की संख्या: 1,87,096
4. उन जीपी की संख्या जहां वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध कराए गए हैं: 1,04,664
5. एफटीटीएच कनेक्शन की संख्या: 2,07,222
6. फाइबर को लीज पर देना: 58,316 किमी
7. भारतनेट बैंडविड्थ को लीज पर देना: 36,19,254 एमबीपीएस
8. प्रति माह डेटा खपत: 5789 टीबी

24. 2022-23 के दौरान दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार के संबंध में लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत बताया:

'देश में दूरसंचार अवसंरचना के विस्तार के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

ड. सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

25. भारतनेट चरण-I को मुख्य रूप से सीएससीई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था जिसके अंतर्गत इसे ग्रामपंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया था। इसके अलावा सीएससी को चरण-II के अंतर्गत बिहार की 2692 ग्राम पंचायतों और 36744 गांवों में 1 वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य भी सौंपा गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 94800 सरकारी संस्थाओं जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों, डाकघरों को पहले ही सीएससी-एसपीवी से जोड़ दिया गया है। यह जानकारी विभाग द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तुत की गई थी। हालांकि, समिति ने नोट किया कि इस बार सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत, समिति ने नोट किया कि यूएसओएफ स्कीमों के तहत सेवा से वंचित लगभग 25000 गांवों में 4जी सैचुरेशन मोबाइल परियोजना शुरू करने के लिए करार पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया जारी है।

26. जब समिति ने विभाग से उपर्युक्त मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा, तो निम्नवत बताया गया:

“यूएसओएफ, बीबीएनएल और सीएससी-एसपीवी के बीच दिनांक 15-07-2019 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार सीएससी-एसपीवी को शेष भारतनेट चरण-I जीपी में 1 वाई-फाई और 5 एफटीटीएच उपलब्ध कराना था। तदनुसार सीएससी-एसपीवी ने लगभग 62,000 वाई-फाई एक्सेस पॉइंट और 1 लाख एफटीटीएच कनेक्शन संस्थापित किए करार के अनुसार सीएससी-एसपीवी को 5 वर्ष के लिए सेवाएं उपलब्ध करानी हैं। इसके अलावा यूएसओएफ तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से संस्थापित वाईफाई/एफटीटीएच कनेक्शनों का भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कर रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।”

27. सचिव, दूरसंचार विभाग ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान बताया है कि:

“भारतनेट अप-टाइम और सीएससी को दी गई परियोजनाओं के बारे में, हमारे पास बहुत सारी जानकारी है जो हम आपको दे सकते हैं. पांच परियोजनाएं हैं जिनके तहत सीएससी को लगभग 4,000 करोड़ रुपये का काम दिया गया है, जिसमें रखरखाव और अंतिम घर तक कनेक्टिविटी और वाई-फाई एक्सेस पॉइंट आदि शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। कुछ परियोजनाएं समापन बिंदु के बहुत करीब हैं।”

च. 6 लाख गांवों को जोड़ने के लिए भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन कार्यनीति

28. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 30.06.2021 को अगस्त 2023 तक देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजीभागीदारी मोड के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन कार्यनीति के लिए अनुमोदन प्रदान किया था। अब भारतनेट का विस्तार आबादी वाले सभी गांवों तक करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधित कार्यनीति में रियायत प्राप्तकर्ता/निजी सेवा प्रदाता द्वारा भारतनेट नेटवर्क का सृजन, उन्नयन, प्रचालन, अनुरक्षण और उपयोग शामिल हैं जिनका चयन वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उपर्युक्त पीपीपी मॉडल के लिए अनुमोदित अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण 16 राज्यों के लिए 19,041 करोड़ रुपये है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के तहत केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों सहित अनुमानित 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। 16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया गया है। हालांकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया और भारतनेट सेचुरेशन के लिए संशोधित कार्यनीति पर अग्रिम चरण में विचार-विमर्श किया जा रहा था।

29. सेवा से वंचित गांवों, जिनके पास कोई दूरसंचार कनेक्टिविटी नहीं है की कुल संख्या और इन गांवों को कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि:

“दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी), दूरसंचार विभाग की फील्ड इकाइयों और राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2022 तक, देश के 6,44,131 गांवों (गांव नंबर 2019 तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल के आंकड़ों के अनुसार हैं) में से लगभग 6,05,230 (~ 94%) गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है और 38,901 गांवों में कोई मोबाइल कवरेज नहीं है। सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) चरणबद्ध तरीके से देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी

प्रदान करते हैं। सरकार सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से फंडिंग के माध्यम से देश के सेवा से वंचित सभी गांवों में मोबाइल नेटवर्क कवरेज प्रदान करने के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। देश भर में ग्रामीण, जनजातीय और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए स्कीमों/परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नवत है:

- देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं का सेचुरेशन। परियोजना की अनुमानित लागत 26,316 करोड़ रुपये है।
- वाम पंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में चरण-II में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। परियोजना की अनुमानित लागत 2,211 करोड़ रुपये है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास कार्यक्रम के तहत देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4जी मोबाइल सेवाओं का प्रावधान। स्कीमों की अनुमानित लागत 3,637 करोड़ रुपये है।
- आकांक्षी जिलों के 7,287 गांवों (आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) में 4 जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान और चार राज्यों (नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजनाओं की अनुमानित लागत 7,152 करोड़ रुपये है।
- जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सीमावर्ती क्षेत्र और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के 354 सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी का प्रावधान। परियोजना की अनुमानित लागत 337 करोड़ रुपये है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेवा से वंचित 85 गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान और राष्ट्रीय राजमार्ग 223 में निर्बाध 4जी मोबाइल कवरेज। परियोजना की अनुमानित लागत 130 करोड़ रुपये है।”

30. समिति ने प्रस्ताव के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारणों और संशोधित कार्यनीति की स्थिति के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। इस पर, अपने लिखित उत्तर में, विभाग ने निम्नवत बताया है:

“उद्योग परामर्श के आधार पर नॉन-रिस्पोसिव बोली प्रक्रिया के प्रमुख कारण नीचे इंगित किए गए हैं:

- राज्यों में कम अनुमानित परियोजना लागत (ईपीसी) के परिणाम स्वरूप परिभाषित थ्रेशोल्ड के कारण व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में कमी आई है।
- परियोजना के लिए व्यवहार्यता सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकरण द्वारा ईपीसी के % के रूप में सीमित व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण और इसका अग्रिम पूंजी संवितरण।
- प्राधिकरण द्वारा रियायत प्राप्तकर्ता को “जैसा है, जहां है आधार पर” अंतरित किए जा रहे मौजूदा भारतनेट नेटवर्क की परिसंपत्तियों (दोषपूर्ण/लॉसी फाइबर) की गुणवत्ता पर न्यूनतम स्पष्टता।
- केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आरओडब्ल्यू शुल्क में कोई छूट नहीं दी गई।
- रियायत अवधि के दौरान निकास खंडों और निकास करने पर परिसंपत्तियों के अंतरण पर स्पष्टता की कमी।
- प्राधिकरण द्वारा “जैसा है, जहां है आधार पर” अंतरित की गई परिसंपत्तियों के संशोधन के लिए वहन किए जाने वाले लागत बोझ पर स्पष्टता का अभाव
- पीपीपी मॉडल के तहत कनेक्टिविटी दायित्वों को पूरा करने के लिए मौजूदा सेवा प्रदाता की ओएफसी परिसंपत्तियों का लाभ उठाने में सीमित छूट
- बड़े पैकेज जिसके अंतर्गत कई राज्य शामिल हैं, के लिए रियायत प्राप्तकर्ता से महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता थी।
- रेलवे, पावर-ग्रिड, राज्य बोर्ड में हवाई केबल रोलआउट के लिए खंभों के उपयोग शुल्क पर कोई छूट प्रदान नहीं की गई थी।
- ग्राम पंचायत/गांव में सरकारी/स्थानीय निकायों से संबंधित भवनों में उपकरणों की संस्थापना के लिए निशुल्क स्पेस की अनुपलब्धता।
- 99% की सख्त एसएलए आवश्यकता के कारण दंड की प्रयोज्यता के साथ उच्च ओपेक्स आवश्यकता होती है।
- बीबीएनएल पोर्टल की तुलना में निविदा दस्तावेजों में बीबीएनएल परिसंपत्तियों से संबंधित आंकड़ों/सूचनाओं में अंतर से बजट/लागत प्रभावित हो रहे हैं।

पीपीपी निविदा में भाग लेने में बाधा उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त कारकों और बाद में हितधारकों के साथ किए गए विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए ईपीसी मोड (डीबीओएम मॉडल) पर भारतनेट परियोजना शुरू करने और कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया।”

31. प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) की प्रतिक्रिया और सभी 6 लाख गांवों को जोड़ने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि:

“प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) 27.01.2022 को खोला गया था। बोली पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और भारतनेट के हिस्से के रूप में एक संशोधित मॉडल तैयार किया जा रहा है और 2025 तक शुरू होने की संभावना है।”

छ. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी):-

32. विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सीटीडीपी के तहत योजनाओं का विवरण निम्नवत है:

पूर्वोत्तर के असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) में कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवाएं और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज: प्रारंभिक दायरे के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश (केवल राष्ट्रीय राजमार्ग) के सेवा से वंचित गांवों और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 2004 टावरों की स्थापना करके मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जानी थी। दिनांक 08.12.2017 को कुल 1655.56 करोड़ रु. की परियोजना लागत के साथ परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड और भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे। दिनांक 30.11.2021 तक, कुल 1,358 साइट स्थापित की जा चुकी हैं और वे सेवाएं प्रदान कर रही हैं। परियोजना ने रोल-आउट और प्रचालन और रखरखाव के चरण को पूरा कर लिया है। राज्यवार विवरण निम्नवत है:

तालिका: योजना की राज्यवार प्रगति

क्र. सं.	राज्य	टावरों की संख्या (करार के अनुसार)	स्थापित टावर और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं	टावरों द्वारा प्रदान किया गया कवरेज	
				कवर किए गए गाँव	कवर किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग
1	असम	983	439	530	25
2	सिक्किम	20	8	9	0

क्र. सं.	राज्य	टावरों की संख्या (करार के अनुसार)	स्थापित टावर और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं	टावरों द्वारा प्रदान किया गया कवरेज	
				कवर किए गए गाँव	कवर किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग
3	मणिपुर	437	404	382	55
4	मिजोरम	246	214	213	17
5	नगालैंड	160	152	112	45
6	त्रिपुरा	9	3	-	3
7	अरुणाचल प्रदेश	149	138	-	138
	कुल	2004	1358	1246	283

(i) कुल उपभोक्ता: 8.37 लाख

(ii) लगभग 372 साइटों को प्रचालक द्वारा मोबाइल कवरेज के पूर्व-अस्तित्व के कारण छोड़ दिया गया है, आबादी दूसरे गाँव में चली गई है आदि और शेष साइटों को विभिन्न कारणों, वन और रक्षा मंजूरी, पहुंच के मुद्दों, भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों, गाँव में बाढ़ आने, गाँव नहीं मिलने, राज्य के बेमेल होने आदि कारणों से स्थापित नहीं किया गया था।

अरुणाचल प्रदेश के सेवा से वंचित गांवों और असम के 2 जिलों में मोबाइल सेवाएं :
अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं के प्रावधान के लिए दिनांक 29.10.2021 को मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के साथ और असम के 2 जिलों के लिए दिनांक 01.11.2021 को मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। परियोजना की कुल लागत 1255.49 करोड़ रु. है। सभी गांवों के सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है। शुरू होने की अवधि अप्रैल 2023 है। परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

करार के अनुसार गांवों की संख्या	करार के अनुसार टावर की संख्या	स्वीकृत विलोपन	शुरू किए गए टावर	कवर किए गए गाँव	
अरुणाचल प्रदेश	1683	980	171	61	97
असम के जिले कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ	691	531	154	99	122

ज. भारतनेट उद्यमी योजना

33. विभाग ने सृजित भारतनेट अवसंरचना के उपयोग की स्थिति निम्नवत प्रस्तुत की है:

क्र.सं.	कार्यान्वयन मॉडल/चरण	सेवा प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायत
1.	भारतनेट चरण-I	1,19,665
2.	भारतनेट चरण-II के तहत राज्य आधारित मॉडल	37,971
3.	भारतनेट चरण-II के तहत सीपीएसयू आधारित मॉडल	17,792
4.	भारतनेट चरण-II के तहत निजी मॉडल	7,358
5.	भारतनेट चरण-II के तहत सेटलाइट पर जीपी	4,503
6.	कुल	1,87,289

क्र.सं.	उपयोग का मोड	वर्तमान स्थिति
1.	उनजीपी की संख्या जहां वाई-फाई एपी के साथ स्थापित किए गए हैं	1,04,664 ग्राम पंचायतें
2.	दिसंबर, 2022 के दौरान प्रति माह कुल डेटा खपत	5789 टीबी
3.	राज्यों द्वारा भारतनेट पर लिए गए फाइबर टू द होम कनेक्शन	2,18,885
4.	लीज पर दिया गया डार्क फाइबर	58,648 कि.मी.
5.	बैंडविड्थ प्रावधान	3619 जीबीपीएस

- भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करके एक लाख एफटीटीएच कनेक्शन के रॉल आउट के लिए बीएसएनएल के पायलट प्रस्ताव के लिए यूएसओएफ द्वारा आईएल और पूंजीगत प्रोत्साहन दोनों के लिए यूएसओएफ से 89 करोड़ रुपये की वित्तीय सस्सिडी के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया है। यूएसओएफ सस्सिडी में 4500 रुपये प्रति एफटीटीएच का पूंजीगत प्रोत्साहन, जिसे बीएनयू को दिया जाएगा और एक वर्ष के लिए प्रति 100 एमबीपीएस आईआईएल सस्सिडी पर 4 लाख रुपये प्रति मिनी-ओएलटी शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ने परियोजना

के अंतर्गत भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करते हुए 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शनों के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पेश किया है जिसके लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। दिनांक 11.01.2023 तक पूरे देश में पायलट आधार पर लगभग 1,11,196 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

- बीबीएनएल ने देश में भारतनेट चरण-I नेटवर्क का उपयोग करके विभिन्न राज्यों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ लगभग 108 करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा इसमें से अखिल भारतीय स्तर पर सेवा प्रदान करने के लिए 6 करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- बीएसएनएल ने बीएसएनएल/बीबीएनएल के फ्रेंचाइजी और राजस्व हिस्सेदारी भागीदारों को ऑन बोर्ड करने के लिए फ्रेंचाइजी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) विकसित की है और 2614 से अधिक फ्रेंचाइजी बनाए गए हैं। बीएसएनएल ने अपनी फ्रेंचाइजी के लिए राजस्व शेयर करार को निम्नवत अंतिम रूप दिया है:-

मॉडल का नाम	राजस्व शेयर		उत्तरदायित्व			
	बीएसएनएल	भागीदार	ओएलटी	ओएनटी	स्प्लिटर	ओएफसी
मॉडल III - क	%70	%30	बीएसएनएल	भागीदार	भागीदार	भागीदार
मॉडल IV -	%50	%50	भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार

- बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत चल रहे संस्थाओं के लिए हाई स्पीड डाटा कनेक्शनों की मांग की मांग को पूरा करने के लिए यूजर मंत्रालयों/विभागों के साथ वार्ता की गई है।
- मांग पंजीकरण पोर्टल '<https://ruralfiber.bsnl.co.in>' विकसित किया गया है और इसे मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है।
- जीपी स्तर तकलाइव नेटवर्क की स्थिति का अवलोकन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल '<https://bharatnetlive.bbnlindia.in/UNMS/INDEX.jsp>' विकसित किया गया है।
- बीएसएनएल ने भारतनेट नेटवर्क पर सरकारी संस्थानों में जीपी स्तर पर एफटीटीएच उपलब्ध कराने के लिए यूजर मंत्रालयों/विभागों को करार/प्रस्ताव का मसौदा परिचालित किया था।
- 8 राज्यों में, राज्य के नेतृत्व वाले एसपीवी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं।

34. ग्रामीण और दूरस्थ भारत में भारतनेट सेचुरेशन परियोजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करते समय निम्नवत बताया गया:

- i. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूएसओएफ के तहत **26,316** करोड़ रुपये की कुल लागत से कवर न किए गए गांवों को **4** जी मोबाइल कवरेज की सैचुरेशन के लिए मंजूरी दी।
- ii. **24,680** गांवों को कवर करने के लिए **16,464** टावरों की स्थापना करके **4** जी सेवाओं का प्रावधान।
- iii. पुनर्वास, नई बस्तियाँ आदि के कारण **20%** अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का अतिरिक्त प्रावधान।
- iv. केवल **2जी/3जी** कनेक्टिविटी वाले **6279** गांवों में मोबाइल नेटवर्क का **4जी** में स्तरोन्नयन।
- v. बीएसएनएल द्वारा गांवों में सर्वेक्षण कार्य/भूमि आबंटन का कार्य प्रगति पर है। परियोजना को **500** दिनों में दिसंबर **2023** तक पूरा करने का लक्ष्य है।

एक लाख एफटीटीएच कनेक्शन के लिए पायलट

- i. भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से एक लाख एफटीटीएच कनेक्शन शुरू करना।
- ii. दिसंबर **2023** तक पांच लाख एफटीटीएच कनेक्शनों के लिए पायलट का विस्तार किया गया।
- iii. यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित पायलट।
- iv. बीएनयू भारतनेट का उपयोग करके एफटीटीएच प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ राजस्व साझेदारी भागीदार के रूप में काम करता है।
- v. **13.02.2023** तक, पायलट परियोजना के तहत बीएसएनएल के साथ राजस्व साझेदारी भागीदार के रूप में **2,396** बीएनयू को ऑन-बोर्ड किया गया है।
- vi. देश भर में लगभग **1,53,990** एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

झ. आकांक्षी जिला योजना

35. विभाग के अनुसार, चार राज्यों (नामत: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) के 112 आकांक्षी जिलों में सेवा से वंचित 502 गांवों के लिए स्कीम (अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान) में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान को अंतिम रूप दे दिया गया है। समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा मार्च, 2021 में निविदा प्रक्रिया के बाद यूपी और एमपी राज्यों के लिए मैसर्स रिलायंस जियो

इन्फोकॉम लिमिटेड , राजस्थान के लिए मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और बिहार के लिए मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को कार्य आवंटित किया गया है। परियोजना की कुल लागत 421.65 करोड़ रु. है। इसे मार्च, 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है। स्थापना कार्य प्रगति पर है। राज्य में अब तक 119 मोबाइल टावर लगाकर 146 गांवों को कवर किया जा चुका है। 4 राज्यों के आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों की राज्यवार सूची:

क्र.सं.	राज्य का नाम	आकांक्षी जिलों की संख्या	कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या	स्थापित किए जाने वाले टावरों की संख्या	कमीशन की गई साइटों की संख्या	कवर किए गए गांवों की संख्या
1	बिहार	5	80	62	23	40
2	मध्यप्रदेश	8	232	194	57	63
3	राजस्थान	5	195	20	19	19
4	उत्तरप्रदेश	6	22	186	20	24
	कुल	24	529	462	119	146

आकांक्षी जिलों के शेष 7,287 गांव (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा)

36. इस परियोजना में 5 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का प्रावधान शामिल है। दिनांक 20.05.2022 को 3 राज्यों के लिए मैसर्स आरजेआईएल और 2 राज्यों के लिए मैसर्स बीएएल के साथ 3765.47 करोड़ रुपये की लागत से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं एवं सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य नवंबर, 2023 है। 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के सेवा से वंचित 7287 गांवों की राज्य-वार सूची निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिलों की संख्या	समझौते के अनुसार गांवों की संख्या	समझौते के अनुसार साइटों की संख्या	कमीशन की गई साइटों की संख्या	कवर किए गए गांवों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3	1218	771	6	16
2	छत्तीसगढ़	8	699	546	11	11
3	ओडिशा	10	3933	2379	2	10
4	झारखंड	19	827	625		
5	महाराष्ट्र	4	610	458		
कुल		44	7287	4779	19	37

ज. वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए योजना

क. एलडब्ल्यूई चरण-I

37. मंत्रिमंडल ने दिनांक 20.08.2014 को आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 10 प्रभावित राज्यों में 2जी प्रौद्योगिकी पर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में एक परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया। परियोजना की स्वीकृत लागत 4214.28 करोड़ रु. है। बताया गया है कि परियोजना पूरी हो चुकी है और इसका राज्य-वार विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	राज्य का नाम	एलडब्ल्यूई चरण-I	
		कुल एलडब्ल्यूई जिले	कार्यात्मकटावर
1	आंध्र प्रदेश	8	62
2	बिहार	22	250
3	छत्तीसगढ़	16	525
4	झारखंड	21	816
5	मध्य प्रदेश	1	22
6	महाराष्ट्र	4	65
7	ओडिशा	19	256
8	तेलंगाना	8	173

क्र.सं.	राज्य का नाम	एलडब्ल्यूई चरण-I	
		कुल एलडब्ल्यूई जिले	कार्यात्मकटावर
9	उत्तर प्रदेश	3	78
10	पश्चिम बंगाल	4	96
	कुल	106	2343

मौजूदा 2जी साइटों के संचालन और अनुरक्षण के विस्तार और एलडब्ल्यूई-1 परियोजना के मौजूदा 2 जी साइटों के 4 जी उन्नयन को 2,426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 27.04.2022 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। समझौते पर हस्ताक्षर विचाराधीन है।

ख. एलडब्ल्यूई चरण -II

38. इसके अलावा, विभाग ने बताया है कि मंत्रिमंडल ने 23.05.2018 को 4072 स्थानों के लिए 7330 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता सहित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परियोजना के दूसरे चरण के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आवश्यकताओं में संशोधन और स्थान में कमी के कारण, परियोजना को बाद में 2,211.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए 2,542 टावरों के लिए मंजूरी दी गई थी। वामपंथी उग्रवाद चरण-II में मोबाइल टावरों की राज्य-वार सूची निम्नवत है:

क्रम सं.	राज्य	जिलों की संख्या	मोबाइल टावरों की संख्या	शुरू किए गए टावरों की संख्या	कवर किए गए गांवों की कुल संख्या
1	आंध्र प्रदेश	9	346		
2	बिहार	7	16		
3	छत्तीसगढ़	15	971	174	184
4	झारखंड	21	450		
5	मध्य प्रदेश	2	23	6	6
6	महाराष्ट्र	3	125	6	6
7	ओडिशा	5	483	98	98
8	तेलंगाना	12	53		
9	उत्तर प्रदेश	1	42		

क्रम सं.	राज्य	जिलों की संख्या	मोबाइल टावरों की संख्या	शुरू किए गए टावरों की संख्या	कवर किए गए गांवों की कुल संख्या
10	पश्चिम बंगाल	5	33		
कुल		80	2542	284	294

देश भर में सेवा से वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं का सेचुरेशन

39. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27.07.2022 को 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत से देश भर के सेवा से वंचित गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाओं के सेचुरेशन के लिए यूएसओएफ वित्त पोषित परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा से वंचित 24,680 गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करेगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा प्रचालकों द्वारा सेवाओं को वापस लेने आदि के कारण अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4जी में अपग्रेड किया जाएगा। बीएसएनएल ने दिसंबर, 2023 तक परियोजना को पूरा करने के लक्ष्य के साथ गांवों का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया है।

V. रक्षा स्पेक्ट्रम: रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क

40. विभाग के अनुसार, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) सरकार द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है, जिसे सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेक्ट्रम को जारी करने के बदले तीनों रक्षा सेनाओं के लिए टर्न-की आधार पर लागू किया जा रहा है। बीएसएनएल दूरसंचार विभाग की ओर से एनएफएस परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के तहत, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), ट्रांसमिशन उपकरण, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, एन्क्रिप्टर, एंड-पॉइंट उपकरण, डेटा सेंटर आदि जैसे विभिन्न नेटवर्क तत्वों से युक्त पूर्ण दूरसंचार नेटवर्क को तीनों सेवाओं की रीढ़ के रूप में देश भर में स्थापित किया जा रहा है। एनएफएस परियोजना अतिरेक के विकल्प के रूप में, जहां भी लागू हो, समर्पित ओएफसी और सैटेलाइट और माइक्रोवेव सहित हाइ एंड संचार और नेटवर्किंग उपकरणों के माध्यम से उच्च बैंडविड्थ प्रदान करती है।

इस योजना का उद्देश्य अत्याधुनिक दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को बढ़ाना है। यह समर्पित, सुरक्षित, लचीला और निरर्थक नेटवर्क के

माध्यम से रक्षा सेवाओं की संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसकी ऑनलाइन निगरानी और यातायात के प्रबंधन सहित एकीकृत त्रि-सेवा नेटवर्क की उपलब्धता आधुनिक युद्ध की वर्तमान अवधारणा में मिशन की महत्वपूर्ण क्षमताओं को मजबूत करेगी और भविष्य के लिए तैयार साइबर युद्ध के माहौल में रक्षा बलों की सुरक्षित संचार आवश्यकता को भी पूरा करेगी।

41. 2019-20 से 2022-23 तक प्रस्तावित, बीई, आरई, वास्तविक, 2023-24 के लिए प्रस्तावित और बजट अनुमान निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपये में)

	20-2019	21-2020	22-2021	वर्ष 23-2022	24-2023
प्रस्तावित	5000	10000	6820	1961	2158
ब अ	4705	5000	5200	1961	2158
सं अ	4705	4000	5200	1961	
वास्तविक	4705	4000	3070	1000	
सं अ से व्यय का प्रतिशत	%100	%100	%59.04	मार्च 2023तक %100की उपलब्धि	

42. लक्ष्यों की तुलना में परियोजना के सभी घटकों के कार्यान्वयन और उपलब्धियों की नवीनतम समग्र स्थिति के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

	लक्ष्य)कुल के % के रूप में(उपलब्धि)कुल के % के रूप में(
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (तीसरी तिमाही तक)	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (तीसरी तिमाही तक)
बिछाई गई ओएफसी	96	95	98	100	100	93	96	97	97.3	97.9
चालू किए गए ओएफसी लिंक	96	91	94	100	100	87	92	94	100	94.0
ऑर्डर दिए गए	100	100	100	100	100	75	100	100	90	100

उपकरण										
संस्थापित उपकरण	20	60	95	100	100	20	55	77	96.3	97

43. बजट अनुमान 2022-23 और 2023-24 के बीच भिन्नता के कारणों और 2023-24 के दौरान धन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित में निम्नवत बताया:

“वर्ष 2021 के दौरान अनुमानित उत्पादन के अनुसार काम पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण महामारी के प्रभाव और अन्य कारणों जिन्हे नीचे पैरा VIII के उत्तर में दर्शाया गया है, से 2130 करोड़ रुपये वापस आ गए। तदनुसार, वर्ष 2022-23 में बजट अनुमान केवल 1961 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया था। अब, परियोजना अपने पूरा होने के अंतिम चरण में है और वर्ष 2023-24 के लिए 2158 करोड़ रुपये की शेष राशि मांगी गई है।”

44. परियोजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने बताया है कि:

“यह परियोजना अत्यधिक जटिल प्रकृति की है जिसमें 60,000 किलोमीटर ओएफसी बिछाना शामिल है। ओवरले उपकरण और अनुप्रयोग, जिसमें कई हितधारकों द्वारा समन्वय, एकीकरण और कार्यान्वयन शामिल है। इस परियोजना को विभिन्न एजेंसियों जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), रेलवे, पीडब्ल्यूडी, वन, वन्यजीव, नगर निकायों आदि जैसी विभिन्न अन्य राज्य एजेंसियों से सैकड़ों 'राइट ऑफ वे' (आरओडब्ल्यू) अनुमतियां प्राप्त करने में कठिनाइयों / देरी का सामना करना पड़ा है। लद्दाख/कश्मीर/अरुणाचल प्रदेश/सिक्किम में सीमित कार्य मौसम, दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों और दुर्गम स्थिति ने भी प्रस्तावित समय सीमा को प्रभावित किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवाजाही में प्रतिबंध के कारण, परियोजना में देरी हो रही है। ग्लोबल चिप शॉर्टेज के कारण विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति, विशेष रूप से एन्क्रिप्टर (एमसीईयू) के घटक में देरी हुई है। सेना ने फाइबर वितरण मॉड्यूल (एफडीएमएस), रमन एम्पलीफायर आदि के समाप्ति के लिए ओएफसी जैसी अतिरिक्त आवश्यकताओं को रखा है। अंतिम समय में इन अतिरिक्त आवश्यकताओं के कारण भी परियोजना में देरी हुई है। मैसर्स बीईएल द्वारा एमसीईयू (एनक्रिप्टर्स) और सेटेलाइट घटक के विनिर्माण/संस्थापना की प्रगति बहुत धीमी है जिसने नौसेना और

सेना की परियोजनाओं को चालू करने को भी प्रभावित किया है। विभिन्न सड़क चौड़ीकरण गतिविधियों ने ओएफसी बिछाने और बाद में नेटवर्क के परिचालन में देरी की है। एनएफएस परियोजना की नियमित अंतराल पर मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाती है। परियोजना की कार्य-प्रगति का पता लगाने के लिए नियमित रूप से बीएसएनएल के सीएमडी/डीडीजी (पीएम) भी परियोजना की समीक्षा करते हैं। सभी बैठकों में रक्षा सेवाओं के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसके अलावा नीति आयोग और एमओएसपीआई भी परियोजना की कार्य-प्रगति की निगरानी करते हैं।

VI. अन्य समकालीन मुद्दे और योजनाएं

i. प्रधान मंत्री-वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी):

45. सचिव, दूरसंचार विभाग ने साक्ष्य के दौरान पीएम-वाणी योजना की प्रगति का विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया है:

“देश भर में लगभग 150 पीडीओ काम कर रहे हैं, और वर्तमान में लगभग 1,44,669 पीएम-वाणी इकाइयां परिचालन में हैं। आज हमारे पास एक डैशबोर्ड है। मुझे लगता है कि इसकी केंद्रीय निगरानी की जाती है। इकाइयों के संचालन की निगरानी की जा रही है और बीडीओ को सहायता प्रदान की जाती है। पीएम-वाणी एक ऐसी योजना बनी रहेगी जिसमें वे केवल ग्रे स्पॉट में काम करेंगे, जहां मुझे लगता है कि इमारतों के अंदर, मॉल के अंदर, शायद हवाई अड्डों में कनेक्टिविटी एक समस्या है। इसलिए, इस प्रकार के गंतव्यों में पीएम-वाणी का बहुत अच्छा अनुप्रयोग होगा। अतः, मेरा मानना है कि वर्तमान में हम बस अड्डों, विमानपतनों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों, सरकारी अस्पतालों और इन सभी प्रकार के स्थानों पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जहां लोग बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और उन्हें संपर्क की आवश्यकता होती है तथा भवनों के भीतर कनेक्टिविटी की मजबूती नहीं होती है। इसलिए, पीएम-वाणी को इस तरह के केन्द्रित ध्यान के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यह एक पूर्ण कवरेज या सार्वभौमिक कवरेज मॉडल नहीं होगा। इसलिए, यह कनेक्टिविटी अंतराल को कवर करने के लिए एक प्रतिबंधित मॉडल होगा।”

46. पीएम-वाणी कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति, आवंटित निधियों, बजट अनुमानों और अन्य विवरणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अनुबंध III में दिए अनुसार विवरण प्रस्तुत किए हैं।

ii. यूनिवर्सल चार्जिंग डिवाइस

47. यूनिवर्सल चार्जिंग डिवाइस को अपनाने के मुद्दे पर दूरसंचार विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान बताया:

'चार्जर्स के बारे में ट्राई ने ग्रीन टेलीकॉम पर एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें वे सार्वभौमिक शुल्क लाने के लिए बाजार के साथ परामर्श भी कर रहे हैं। इसी तरह, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने भी मोबाइल सेवा प्रदाताओं के साथ चर्चा शुरू की ताकि हर कोई एक ही चार्जर को अपना सके और आपको विभिन्न मोबाइल उत्पादों के लिए बार-बार एक ही चार्जर न खरीदना पड़े। दोनों इस पर काम कर रहे हैं।'

48. जब विभाग से यूनिवर्सल चार्जर पर वैश्विक रूप से हो रही चर्चा पर उनके विचार पूछे गए, तो विभाग ने निम्नवत बताया:

“वर्तमान में मोबाइल फोन से संबंधित मुद्दों को एमईआईटीवाई देख रहा है। हालांकि मोबाइल फोन के लिए सार्वभौमिक चार्जर (सिंगल सी-टाइप चार्जर) के बारे में यह उल्लेख किया गया है कि आईटीयू-टी ने एक सिफारिश एल.1000 (07/2019) जारी की है जो मोबाइल फोन के लिए सार्वभौमिक चार्जर निर्धारित करती है जिसे अभी तक भारत में अनिवार्य नहीं किया गया है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय इस मुद्दे पर एमईआईटीवाई और उद्योग के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। इसके अलावा ट्राई ने इस मुद्दे को कवर करके ग्रीन टेलीकॉम पर परामर्श पत्र जारी किया है और इस पर जल्द ही सिफारिशें तैयार की जाएंगी।

VII. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा

i. बीएसएनएल, एमटीएनएल और ITI का प्रदर्शन

49. विभाग द्वारा प्रस्तुत बीएसएनएल के राजस्व और कार्य व्यय का विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिनांक 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार)	2023-24 (प्रस्तावित)
कुल आय लक्ष्य	20,000	18,000	25,411	17,161	21,908
कुल आय	18,907	18,595	19,053	9,366	21,908
कुल व्यय	34,406	26,036	26,034	13,429	29,674
निवल लाभ/हानि	-15,500	-7,441	-6,982	-3589	-7,766

नोट: आय लक्ष्य डीपीई द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से सौंपा गया है। वित्त वर्ष 21-22 के लिए, कुल आय के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अन्य वर्षों के लिए प्रचालन से राजस्व के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे

50. जब इस तथ्य के मद्देनजर कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी लागू की जानी है, बीएसएनएल द्वारा 4 जी शुरू करने के मुद्दे के बारे में पूछा गया तो दूरसंचार विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष निम्नवत बताया:

'महोदय, जैसा कि आपने देखा है, डेटा दूरसंचार कंपनियों की सफलता की कुंजी है। इसलिए, जितना अधिक डेटा दूरसंचार नेटवर्क में प्रवाहित होता है, वह उतना ही अधिक राजस्व बनाता है। इसलिए, बीएसएनएल 4 जी पर स्विच करने में असमर्थता के कारण पीछे छूट गया है। अब, मुझे लगता है कि भारतीय दूरसंचार स्टैक सफलतापूर्वक सिद्ध हो गया है, और हम इसे अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में हैं। जो भी तकनीक हम 5-जी सक्षमता के रूप में अपनाने जा रहे हैं, जहां मुझे लगता है कि हम 5 जी पर भी स्विच कर सकते हैं, जिसके बारे में मुझे लगता है कि मेरे सहयोगी विस्तार से बताएंगे।'

51. विभाग द्वारा प्रदान किए गए अनुसार पिछले 3 महीनों के लिए विभिन्न टीएसपी के उपयोगकर्ताओं द्वारा डेटा खपत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत है:

अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक टेरा बाइट्स (टीबी) में टीएसपी वार कुल डेटा उपयोग (लगभग)				
क्र.सं.	टीएसपी का नाम	अक्टूबर-2022	नवंबर-2022	दिसंबर-2022
1	भारती एयरटेल लिमिटेड	4432945.38	4296202.876	4486296.332
2	बीएसएनएल	113848.302	108532.5401	112788.9298
3	एमटीएनएल	423.734629	419.8377637	461.186709
4	आरसीएल/आरटीएल	1	1	25
5	रिलायंस जिओ	7588850.12	7225584.381	7585833.07
6	वोडाफोन आइडिया	1872469.9	1786630.678	1872725.09
	कुल	14008538	13417371	14058130

52. समिति ने जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के निवल घाटे को कम करने के लिए कोई समय सीमा तय की है। इसके लिखित उत्तर में, निम्नवत बताया गया है:

“मंत्रिमंडल द्वारा जुलाई, 2022 में अनुमोदित बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना में परिकल्पना की गई है कि 4जी सेवाओं, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के तहत स्वदेशी विकास कार्यक्रम के अधीन है, के शुभारंभ से बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और वित्त वर्ष 2026-27 में लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। एमटीएनएल के अस्थायी ऋणको देखते हुए परिसंपत्ति मुद्रीकरण, एजीआर बकाया, ऋण का भुगतान और एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय के लिए आगे की कार्रवाई जैसे मामलों को सचिव समिति (सीओएस) के समक्ष उठाया जाएगा ताकि दूरसंचार पीएसयू के पुनर्गठन और प्रचालन एकीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करने की सिफारिश की जा सके और इस समिति में सचिव-व्यय, सचिव-दूरसंचार, सचिव-डीआईपीएएम और सचिव-सार्वजनिक उद्यम विभाग शामिल हैं। बीएसएनएल ने विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करने के लिए ट्रांजेक्शन सलाहकार नियुक्त किया है। ट्रांजेक्शन सलाहकार ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।”

वित्त वर्ष **2023-24** के लिए बीएसएनएल के राजस्व, व्यय और हानि के संबंध में निम्नलिखित अनुमान लगाया गया है:-

क्र.सं	ब्यौरा	राशि करोड़ रुपये में
क	कुल राजस्व)भूमि और अन्य आय की बिक्री से लाभ सहित(21,908
ख	व्यय)वेतन, लाइसेंस शुल्क और ओपेक्स(20,069
ग	ईबीआईटीडीए =) क-ख)	1839
घ	मूल्यहास और वित्त लागत	9605
	निवल हानि)ग-घ)	(7766)

इसके अलावा, विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल के अनुमानित राजस्व और व्यय के बारे में निम्नलिखित विवरण प्रदान किए हैं।

बीएसएनएल:

(करोड़ रु. में)

विवरण	2023-24
परिचालन से राजस्व	20,008
भूमि मुद्रिकरण (बिक्री से लाभ)	600
अन्य आय	1,300
कुल आय (क)	21,908
कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ	7,939
मूल्यहास (x)	7,005
लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क	1,716
एडमिन, संचालन और अन्य खर्च	10,414
वित्तीय व्यय (y)	2,600
कुल व्यय (b)	29,674
ईबीआईटीडीए z= (a-b+x+y)	1,839
लाभ/ (हानि) (क-ख)	-7,766

इसके अलावा, यह बताया गया कि:

“बीएसएनएल ने विगत में वृहद्ध जनशक्ति लागत, 4जी सेवाओं की कमी और नेटवर्क के विस्तार/उन्नयन के लिए निवेश की कमी के कारण लगातार निरंतर घाटा सूचित किया है। हालांकि वर्ष 2023-24 में स्पेक्ट्रम आवंटन और 4जी सेवाओं की शुरुआत होने

की उम्मीद है तथा वर्ष 2024-25 और उसके बाद राजस्व में अत्यधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने कंपनी के लिए व्यापक पुनरुद्धार पैकेज के लिए अनुमोदन दिया है। कंपनी वर्ष 2020-21 से ईबीआईटीडीए सकारात्मक है। पुनरुद्धार पैकेज का पूर्ण कार्यान्वयन होने पर कंपनी को वर्ष 2026-27 के लिए निवल लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।”

एमटीएनएल:

पुनरुद्धार योजना में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएनएल के लिए ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। हालांकि बजट अनुमानों के अनुसार वर्ष 2023-24 में 2808 करोड़ रुपये का निवल घाटा होगा।

विभाग ने यह भी बताया कि:

“एमटीएनएल परिसंपत्ति मुद्रीकरण लागू कर रहा है जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना में ऋण को कम करने के लिए मुख्य स्रोत के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा एमटीएनएल को राजस्व को बनाए रखने और इसमें वृद्धि करने के लिए कैपेक्स वित्तपोषण की आवश्यकता होगी। तथापि दूरसंचार विभाग के दिनांक 02.08.2022 (पैरा 2.7) के अनुसार एमटीएनएल के अस्थाई ऋण को ध्यान में रखते हुए परिसंपत्ति मुद्रीकरण, एजीआर बकाया, ऋण का भुगतान और एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय के लिए आगे की कार्रवाई जैसे मामलों के समाधान के लिए आगे विस्तृत जांच के लिए सचिव समिति (सीओएस) का गठन किया गया है जिसमें सचिव डीओई, सचिव दूरसंचार विभाग, सचिव डीआईपीएएम और सचिव डीपीई शामिल हैं। वित्त मंत्री और संचार मंत्री को भावी कार्यनीति निर्धारित करने का अधिकार होगा।”

53. विभाग से स्वदेशी 4 जी उपकरणों की खरीद की पूरी प्रक्रिया, जिसे शुरू करने और कार्यात्मक बनाने की संभावना है के पूरा होने के बारे में पूछे जाने पर निम्नवत जानकारी प्रदान की गई थी:

“बीएसएनएल ने दिनांक 01.01.2021 को 'पंजीकरण सह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' (पीओसी) के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की ताकि भारतीय कंपनियां इसके आगामी 4जी टेंडर में भाग ले सकें। मैसर्स टीसीएस ने पीओसी के लिए अपने

उपकरण लगाए। इसके बाद, बीएसएनएल ने दिनांक 22.10.2022 को मैसर्स टीसीएस और मैसर्स आईटीआई (आरक्षण कोटा के तहत 20% मात्रा के लिए) को 4जी आवश्यकता के लिए निविदा जारी की। बीएसएनएल द्वारा मैसर्स टीसीएस और मैसर्स आईटीआई की तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियां दिनांक 23.11.2022 को खोली गईं। इसके बाद वित्तीय बोलियां दिनांक 13.01.2023 को खोली गईं। जुलाई, 2022 के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, मंत्री समूह (जीओएम) खरीद की प्रक्रिया को अनुमोदित करेगा। इसके बाद बीएसएनएल खरीद को अंतिम रूप देगी। देश में पहली बार 4जी स्टैक के स्वदेशी विकास और चिपसेट की आपूर्ति श्रृंखला में समस्याओं के कारण, तैनाती धीरे-धीरे शुरू होगी और सभी 1 लाख साइटों की परियोजना को पूरा करने में 2 वर्ष लगने की संभावना है।”

ii. परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण और पूंजी निवेश

54. समिति द्वारा परिसंपत्तियों और मुद्रिकृत मूल्य के चल रहे मुद्रिकरण के बारे में पूछे जाने पर बीएसएनएल के सीएमडी ने निम्नवत जानकारी प्रदान की:

‘महोदय, बीएसएनएल पहले से ही निर्मित इमारत में खाली जगह का उपयोग किराए के लिए कर रहा है। पिछले साल, हमने किराये की आय से 212 करोड़ रुपये कमाए। इस वर्ष यह आंकड़ा 260 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इसी प्रकार, एमटीएनएल में हमने किराये की आय के रूप में लगभग 350 करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। महोदय, हमने लगभग 200 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का मुद्रिकरण किया है। संपत्ति का मूल्य 67,000 करोड़ रुपये है। हमने बीएसएनएल में मुद्रिकरण के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों और मुद्रिकरण के लिए 18,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की पहचान की है। 100 करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियां एनएलएमसी के माध्यम से की जाती हैं और 10 करोड़ रुपये से कम की परिसंपत्तियां बोर्ड द्वारा की जाती हैं। हमने मुद्रिकरण के लिए पहले ही लगभग 30 परिसंपत्तियों की बोली आमंत्रित की है। सात संपत्तियों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं।”

55. उपलब्ध परिसंपत्तियों के पुनः उपयोग से दूरसंचार विभाग/बीएसएनएल/एमटीएनएल द्वारा अर्जित राजस्व का विवरण तथा बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के मुद्रिकरण के

लिए उपलब्ध चिन्हित परिसम्पत्तियों के विवरण राज्य-वार उपलब्ध कराने के लिए कहे जाने पर विभाग ने निम्नवत विवरण उपलब्ध कराया:

बीएसएनएल:-

नीचे मुद्राकरण क्षेत्रों के लिए पहले से ही चिन्हित बीएसएनएल भूमि और भवन परिसंपत्तियों की राज्य-वार सूची। इनके अलावा, बीएसएनएल मुद्राकरण के लिए और अधिक परिसंपत्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

परिसंपत्तियों के पुनः उपयोग के लिए, बीएसएनएल अपने अधिशेष निर्मित स्थान को पट्टे पर दे रहा है और वित्त वर्ष **2022-23** में **31** जनवरी, **2023** तक अर्जित राजस्व **202** करोड़ रुपये है।

मुद्राकरण के लिए पहचान की गई बीएसएनएल की भूमि और भवन परिसंपत्तियों की सूची अनुबंध-IV के अनुसार है।

एमटीएनएल:-

एमटीएनएल की किसी भी भूमि परिसंपत्ति का आज तक बिक्री के माध्यम से मुद्राकरण नहीं किया गया है। हालांकि, एमटीएनएल ने वित्त वर्ष **2022-23** में जनवरी **2023** तक संपत्तियों के किराये से **321** करोड़ रुपये (लगभग) और पिछले पांच वर्षों (**2018-19** से **2022-23** से जनवरी **2023** तक) में **1732** करोड़ रुपये (लगभग) का राजस्व अर्जित किया है।

2019 में कैबिनेट की मंजूरी के समय, एमटीएनएल ने दिल्ली और मुंबई क्षेत्र में मुद्राकरण के लिए **52** भूमि पार्सल और **494** क्वार्टर और **7** एससीओ की पहचान की और इन संपत्तियों के लिए राष्ट्रपति का आदेश भी दिया गया था (प्रतिलिप संलग्न)।

तथापि, मुम्बई में एमटीएनएल की अधिकांश परिसम्पत्तियों में आरक्षण/आदेश की समस्या है हैं अर्थात भूमि का आबंटन एजेंसी/राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन/उपयोग के लिए किया गया है। दिल्ली में, अधिकांश संपत्तियां डीडीए से आवंटित की जाती हैं और संस्थागत श्रेणी में हैं। ये समस्याएं इन संपत्तियों के

मुद्रीकरण में बाधा डाल रहे हैं। एमटीएनएल आरक्षण और आदेश को हटाने के लिए स्थानीय निकायों/महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत कर रहा है।

56. जब समिति ने बीएसएनएल के राजस्व और अतिरिक्त राजस्व के स्रोत के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की तो बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने समिति के समक्ष निम्नवत जानकारी दी:

“मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ। पिछले साल मेरा राजस्व 11,148 करोड़ रुपये था। इस वर्ष, दिसंबर तक - मैं इसी अवधि के आंकड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ - यह 12,759 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,600 करोड़ रुपये अधिक है। राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल ब्याज, कर, मूल्यहास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले मेरी आय इस अवधि में 470 करोड़ रुपये थी। चालू नौ महीने की अवधि में यह 755 करोड़ रुपये है। इसलिए, राजस्व के संदर्भ में, व्यवसाय के लगभग सभी क्षेत्रों में, 4 जी नहीं होने के बावजूद, मोबाइल सहित इसमें वृद्धि हुई है। बीएसएनएल पिछले नौ महीनों में 4जी नहीं होने के बावजूद राजस्व में 1,600 करोड़ रुपये की वृद्धि करने में सक्षम है। इसलिए, हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, दो बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्र हैं जिनमें मैं विकास कर रहा हूँ। मेरा एफटीटीएच व्यवसाय काफी बढ़ रहा है। मैं उस पर आंकड़े देना चाहूंगा। पिछले नौ महीनों की इसी अवधि में मेरा मोबाइल राजस्व 3,900 करोड़ रुपये था। इस साल यह 4,248 करोड़ रुपये है। एक अन्य क्षेत्र जहां वृद्धि देखी जा सकती है, वह फाइबर टू होम व्यवसाय है जहां मेरा राजस्व 1,119 करोड़ रुपये था। यह 1,506 करोड़ रुपये हो गया है।”

57. राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया गया कि:

“कैपेक्स और स्पेक्ट्रम के प्रति सरकार के समर्थन के साथ बीएसएनएल निविदा को अंतिम रूप देने के बाद पूरे भारत में 4जी सेवाएं शुरू करेगा। 4जी सेवाओं की शुरुआत से कंपनी को उपभोक्ता आधार, एआरपीयू और मोबाइल सेवाओं से राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।

कंपनी ने भारतनेट नेटवर्क का उपयोग करते हुए एफटीटीएच आधार का विस्तार करने के लिए कदम उठाए हैं। यह राजस्व बढ़ाने के लिए लीज्ड लाइन उपभोक्ताआधार बढ़ाने और टावरों और खाली जगहों और भवनों के मुद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

एमटीएनएल:

वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएनएल का अनुमानित राजस्व और व्यय क्रमशः 1750.00 करोड़ रुपये और 4970.78 करोड़ रुपये है।

58. बीएसएनएल/एमटीएनएल के 2022-23 के दौरान राजस्व लक्ष्य, प्राप्त उपलब्धियों और लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाने के कारणों के बारे में विवरण प्रस्तुत करते समय निम्नवत बताया गया:

“बीएसएनएल:

वित्त वर्ष 22-23 के लिए प्रचालन से राजस्व का लक्ष्य 17,161 करोड़ रुपये है जिसके तहत सितंबर 2022 तक 8321 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जा चुका है । बीएसएनएल को वित्त वर्ष 2022-23 के वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है।

एमटीएनएल

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2022-23
कुल आय लक्ष्य	1810.00
कुल वास्तविक आय (सितंबर -22 तक)	775.89

लक्ष्यों प्राप्त न कर पाने के कारण इस प्रकार हैं:

एक कंपनी के रूप में, एमटीएनएल ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को शामिल करके और ग्राहक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाकर अपने नेटवर्क का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। कंपनी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के तरीकों और साधनों की तलाश कर रही है।

दूरसंचार में तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों और रुझानों ने कई चुनौतियां पेश की हैं। दिल्ली और मुंबई व्यावसायिक रूप से दो बहुत महत्वपूर्ण शहर होने के नाते,

एमटीएनएल को अधिकतम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियों के साथ बुनियादी सेवाओं में प्रतिस्पर्धा ने अत्यधिक चुनौतियां पेश की हैं। एमटीएनएल अपनी स्थिति और ग्राहकों को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।

अपनी स्थापना के बाद से, एमटीएनएल देश के वित्तीय और राजधानी शहरों के विकास का पर्याय और उत्प्रेरक रहा है। कभी इसे दिल्ली और मुंबई की जीवन-रेखा कहा जाता था। तथापि, वर्ष 2009-10 एमटीएनएल के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, जब 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए लगभग 11,097.97 करोड़ रुपये के भुगतान और वेतन संशोधन (वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण) का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करने के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इन खर्चों ने न केवल कंपनी के लगभग 5000 करोड़ रुपये के रिजर्व धनराशि को खत्म कर दिया, बल्कि कंपनी को लगभग 7,533.97 करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण लेने के लिए मजबूर किया। कंपनी को 2009-10 में पहली बार घाटा हुआ था और तब से बढ़ते कर्ज के कारण लगातार घाटे में चल रही है।

इस कमी का प्रमुख कारण यह है कि एमटीएनएल गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है और अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धनराशि की व्यवस्था/जुटाने की स्थिति में नहीं है। बाजार के लिए तैयार प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान करने के लिए एमटीएनएल में मौजूदा नेटवर्क अवसंरचना के उन्नयन और नए नेटवर्क घटकों की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है। हालांकि, दिनांक 02.08.2022 के डीओटीओएम के अनुसार बीएसएनएल को एमटीएनएल के लिए वित्त वर्ष 22-23 से वित्त वर्ष 24-25 के लिए कैपेक्स के लिए 1851.2 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई सर्किल सहित भारत में 4जी/5जी नेटवर्क शुरू करेगा।

इन तथ्यों को विस्तृत ढंग से व्यक्त करने वाले कुछ बिंदु निम्नवत हैं:

- **सीमित बाजार क्षेत्र** :एमटीएनएल का प्रचालन दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित है और इसलिए कारोबार योजना का दायरा भी सीमित ही है।
- **अधिक संतृप्त बाजार**: दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार बाजार में एक प्रचालक से दूसरे प्रचालक में उपभोक्ताओं के अंतरित होने के अलावा कोई नया उपभोक्ता

नहीं जोड़ा गया है। दिल्ली में मौजूदा टेली-घनत्व %250से अधिक है और मुंबई में मौजूदा टेली-घनत्व %150 से अधिक है।

- **अति प्रतिस्पर्धा:** दिल्ली और मुंबई में 4 से 5 प्रचालक दूरसंचार सेवाएं) वायर लाइन और वायरलेस सहित (प्रदान कर रहे हैं जिसके कारण अति प्रतिस्पर्धी दूर संचार बाजार का सृजन हो रहा है।
- **घटते टैरिफ:**अति प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य के कारण टैरिफ घट रहे हैं और प्रचालक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए असीमित वॉयस और डेटा के साथ-साथ मुफ्त लंबी अवधि के प्रमोशनल ऑफर दे रहे हैं।
- **ग्राहकों की मानसिकता में बदलाव:** पारंपरिक लैंडलाइन से वायरलेस टेलीफोनी और वायरलेस ब्रॉडबैंड में अंतरण।
- **उच्च कैपेक्स और ओपेक्स लागत:** दिल्ली और मुंबई के लिए कैपेक्स और ओपेक्स की लागत सबसे अधिक है। साइट अधिग्रहण के लिए लाइसेंस, आरओडब्ल्यू प्रभार और किराये की लागत देश के अन्य स्थानों की तुलना में दिल्ली और मुंबई में सबसे अधिक है।
- **तेजी से बदलती प्रौद्योगिकियाँ:** दूरसंचार क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही हैं। पिछले 20 वर्षों में जब से देश में मोबाइल सेवा शुरू की गई है तब से अब तक प्रौद्योगिकी 2जी से 5जी में बदल गई है।”

59. विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के कुल बकाया ऋण का विवरण निम्नवत प्रदान किया है:

बीएसएनएल:

दिनांक 31.12.2022 कीस्थितिकेअनुसारबीएसएनएल पर कर्ज**33,339 करोड़ रुपये** है।

(रुपए करोड़ में)

बैंकों से सावधि ऋण	16,191
बांड -सीरीज) नवंबर 2020में जारी*(8,500
बांड -सीरीज) दिसंबर 2022में जारी*(4,185
बैंक ओवरड्राफ्ट	4,463
कुल उधार	33,339

*संप्रभु गारंटी बांड

एमटीएनएल:

दिनांक 31/01/2023 तक एमटीएनएल पर कुल ऋण केवल 28581 करोड़ रुपये हैं।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड

60. आईटीआई में आय और व्यय का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24#
प्रचालन से लक्षित राजस्व (निवल)	3300	2600	2723	2569	2906
प्रचालन से वास्तविक राजस्व (निवल)	2059	2362	1861	364*	-
अन्य आय	184	161	254	32*	65
कुल आय	2243	2523	2115	396*	2972
कुल व्यय	2095	2512	1994	596*	2853
निवल लाभ/हानि	147	11	121	(200)*	119

* दिनांक 30.09.2022 की स्थिति के अनुसार आंकड़े

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान

61. आईटीआई के राजस्व और व्यय की मदों का मुख्य स्रोत;

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत	
प्रचालन से राजस्व	करोड़ रु. में
एस्कॉन-फेज IV	599.57
ई-टेंडरिंग	30.37
महानेट	283.74
जीएसएम	99.59
रक्षा	271.08
आईटी उत्पाद	210.57
इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपकरण	19.92
ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर केबल)	114.38
एनएफएस (स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क)	104.88
गुजनेट	63.08
एलईडी स्ट्रीट लाइट	16.03
डेटा सेंटर	22.91
आईटी व्यवसाय	36.92

जी-पॉन (G-PON) (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क)	7.32
सौर पेनल	13.73
अन्य	183.41
कुल	2,077.48
घटाएं: जीएसटी	216.75
प्रचालन से निवल राजस्व	1,860.73
अन्य आय	
ब्याज - अन्य	4.85
किराया	19.29
राजस्व अनुदान सहायता	214.29
एसडब्ल्यूआर/एनएचएआई द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा	3.44
अन्य	12.69
कुल अन्य आय	254.57
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल आय	2,115.30

व्यय की मुख्य मदें	
विवरण	करोड़ रु. में
सामग्री की खरीद	721.35
स्थापना और रखरखाव पर शुल्क	713.91
कर्मचारियों की लागत	222.18
मूल्यहास	50.03
वित्त लागत	192.13
प्रशासन लागत	43.81
विनिर्माण लागत	47.13
बिक्री लागत	3.70
कुल	1,994.24
अवधि के लिए लाभ	121.06

62. वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व लक्ष्य, प्राप्त उपलब्धियों और लक्ष्य को पूरा न करने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

“वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व लक्ष्य 2569 करोड़ रुपये है। सितंबर 2022 तक उपलब्धि 364 करोड़ रुपये है। आईटीआई वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को मार्च 2023 के अंत तक प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

लक्ष्य पूरा नहीं करने के कारण :

- समय सीमा अधिक हो जाने के कारण कच्चे माल की उपलब्धता में देरी हो रही है।
- कार्यशील पूंजी की कमी।
- एएससीओएन-IV परियोजना में पीओसी (अवधारणा का साक्ष्य) के पूरा होने में देरी।
- ग्राहकों से अनुमोदन, उत्पाद प्रमाणन प्राप्त करने में देरी।
- आरओडब्ल्यू (मार्गाधिकार), टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन में फॉरेस्ट क्लीयरेंस और रोड-वाइडनिंग के मुद्दे।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उत्पादों के पुराने/अप्रचलित हो जाने की उच्च दर।”

63. विभाग ने राजस्व अर्जन बढ़ाने में आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों को भी रेखांकित किया है:

- कोविड-19महामारी की स्थिति के कारणकच्चे माल की उपलब्धता में देरी, खरीद में अधिक समय, श्रमशक्ति की अनुपलब्धता और परिवहन और लॉजिस्टिक्स में बाधाएं और रोस्टर सिस्टम/लॉक डाउन के कारण काम के घंटों में कमी।
- ग्राहकों से वसूली में देरी।
- सीमित नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी की कमी।
- बाजार में निजी दूरसंचार विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उत्पादों के पुराने/अप्रचलित हो जाने की उच्च दर।

64. विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित राजस्व और व्यय तथा राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

परिकल्पित कार्यनिष्पादन	(करोड़ रु. में)
जीएसटी सहित टर्नओवर (क)	3,141.59
संचालन से राजस्व (नेट) (ख)	2,906.43

अन्य आय (ग)	65.00
कुल राजस्व (घ = ख + ग)	2,971.43
सामग्री की लागत	2,337.73
कर्मचारी लागत	223.80
अन्य व्यय	86.00
कुल प्रचालन व्यय	2,647.53
ईबीआईटीडीए (EBITDA)	258.90
वित्तीय लागत	155.00
नकद प्रचालन लाभ/हानि	103.90
मूल्यहास	50.00
कुल व्यय (ई)	2,852.53
निवल लाभ (डी-ई)	118.90

आईटीआई की पूंजी के तहत निधियों के उपयोग का विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रु. में)

प्रस्तावित/बजट अनुमान(बीई)/ संशोधित अनुमान (आरई)/वास्तविक	2019-20	2020-2021	2021-22	2022-23	2023-24
प्रस्तावित	405	385	300	365	220
बजट अनुमान(बीई)	105	105	80	200	160
संशोधित अनुमान (आरई)	105	105	80	187	शून्य
वास्तविक	105	105	71.56	80	शून्य
संशोधित अनुमान (आरई) के संबंध में %	100	100	89	43	शून्य

65. समिति द्वारा 2022-23 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान पर निधियों के आवंटन में वृद्धि/कमी के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने इसके निम्नवत कारण बताए हैं

“वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 200 करोड़ रुपये की कैपेक्स निधि आवंटित की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में 187 करोड़ रुपये के

आवंटन के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसमें से 80 करोड़ रुपये की राशि आईटीआई को सीडीओटी प्रौद्योगिकी की 4जी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वितरित की गई है, यह कार्य प्रगति पर है। शेष परियोजनाओं के लिए, बकाया कैपेक्स का उपयोग करने से पहले आईटीआई अन्य विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।”

66. समिति द्वारा 2022-23 के दौरान लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने इसके लिए निम्नवत कारण बताया:

“वर्ष 2022-23 के बजट अनुमानों में 200 करोड़ रुपये की कैपेक्स निधि आवंटित की गई थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमानों में 187 करोड़ रुपये के आवंटन के अनुरूप संशोधित किया गया है। इसमें से 80 करोड़ रुपये की राशि आईटीआई को सीडीओटी प्रौद्योगिकी की 4जी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वितरित की गई है, यह कार्य प्रगति पर है। शेष परियोजनाओं के लिए, बकाया कैपेक्स का उपयोग करने से पहले आईटीआई अन्य विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है।”

67. विभाग ने 2023-24 के लिए निम्नलिखित निवेश योजना प्रदान की है, बजट अनुमान में प्रस्तावित और आवंटित राशि:

“आईटीआई ने बजट अनुमान 2023-24 में 220 करोड़ रुपये लिए अनुरोध किया है और 2023-24 के लिए बजट अनुमान 160 करोड़ रुपये निर्धारित है। 220 करोड़ रुपये की कैपेक्स राशि की एवज में नियोजित परियोजनाओं का विवरण निम्नवत है।

क्र.सं.	परियोजनाएं	इकाई	बीई 2023-24 कैपेक्स आवश्यकता करोड़ रुपये में	टिप्पणियां
1	सौर सेल निर्माण चरण 1	एनएनआई	90.00	आईटीआई 250 मेगावाट का सोलर सेल मैनुफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना बना रहा है।
2	डिजिटल मोबाइल रेडियो के लिए विनिर्माण इन्फ्रा - डीएमआर	बीजीपी	15.00	आईटीआई डीएमआर विकसित कर रहा है। प्रोटोटाइप जनवरी 2023 तक तैयार हो जाएगा। डीएमआर के थोक उत्पादन के

				लिए इन्फ्रा के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपये की आवश्यकता है।
3	ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विस्तार-पीएच ।	आरबीएल	71.50	आईटीआई ओएफसी के उत्पादन में प्रतिस्पर्धी बने रहने और अन्य ओएफसी निर्माताओं को फाइबर की आपूर्ति करने के लिए फाइबर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
4	ड्रोन का पता लगाना और बेअसर करना Ph I	बीजीपी	8.50	आईटीआई ने ड्रोन डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम के विकास की योजना बनाई है।
5	बिजली की खपत को कम करने के लिए डाटा सेंटर के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र	बीजीपी	15.00	बिजली की खपत को कम करने के लिए आईटीआई डेटा सेंटर के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है।
6	सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो	बीजीपी	20.00	आईटीआई सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकसित करने की योजना बना रहा है
	कुल		220.00	

इस कमी (शार्टफाल) को सितंबर 2023 तक होने वाले वास्तविक व्ययों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। । ”

68. विभाग ने पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली निम्नलिखित प्रमुख बाधाओं और समस्याओं को दूर करने के लिए किए गए उपायों को रेखांकित किया है:

"पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाएं निम्नवत हैं:

- प्रमुख ग्राहक से आदेशों प्राप्त न होना।
- कार्यशील पूंजी की कमी।
- कच्चे माल की अनुपलब्धता, घटकों की खरीद के लिए लगने वाला लंबा समय, कोविड-19 महामारी के कारण लॉजिस्टिक संबंधी बाधाएं।

- एससीओएन चरण IV परियोजना के लिए पीओसी को पूरा करने और परियोजना के भावी रोलआउट में देरी के कारण।
- पीओसी में देरी के कारण बीएसएनएल द्वारा पीओ प्लेस करने में देरी हुई।
- विभिन्न ग्राहकों से भुगतान की वसूली में देरी।
- आरओडब्ल्यू, फारेस्ट क्लीयरेंस और सड़क चौड़ीकरण कार्यों आदि जैसे मुद्दे।

समस्याओं के समाधान के लिए निम्नवत उपाय किए गए हैं

- आईटीआई अनुमानित टर्नओवर हासिल करने के लिए एससीओएन-IV, टीएनएफआईएनईटी, बीएसएनएल 4जी, एयरफोर्स आदेश जैसी प्रमुख परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है।
- माइक्रो पीसी, लैपटॉप, एचडीपीई, ओएफसी जैसे आईटीआई उत्पादों के विपणन पर ध्यान केंद्रित करना और रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए सौर पैनलों की ईपीसी (इंजीनियरिंग, खरीद, और विनिर्माण) कार्य/गतिविधियां प्रारम्भ करना।
- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम), डिजिटल मोबाइल रेडियो (डीएमआर) और एनक्रिप्टर्स जैसी भारी बाजार मांग वाले नए उत्पादों को विकसित करना।
- आईटीआई वोडाफोन, एयरटेल को एचडीपीई, ओएफसी उपलब्ध कराने हेतु निजी ऑपरेटरों के साथ व्यवसाय में भागीदार बनने हेतु सक्रिय प्रयास कर रहा है।
- बीएसएनएल, रेलवे, रक्षा और उद्यमी ग्राहकों आदि के लिए 4जी रेडियो का निर्माण।
- उद्यम और पीएसयू के लिए इलेक्ट्रॉनिक संयोजन और विनिर्माण सेवा।
- क्लाउड आधारित और सुरक्षा सेवा जैसे आईटीआई डाटा सेंटर के माध्यम से उन्नत सेवाओं की पेशकश।
- कार्यशील पूंजी की कमी को वर्तमान में बैंकों से कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा प्राप्ति के माध्यम से प्रबंधित किया जा रहा है।
- आईटीआई भावी प्रौद्योगिकी/उत्पाद जैसे सुरक्षा संचालन केंद्र (साइबर सुरक्षा), 4जी/5जी आदि के लिए टीसीएस (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज), टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, सी-डॉट जैसे अग्रणी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ कार्य कर रहा है और उनके साथ सहबद्ध है।”

69. आईटीआई पुनरुद्धार योजना के तहत आईटीआई लिमिटेड को सरकार द्वारा दी गई समस्त सहायता (पूंजी और राजस्व) के विवरण के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर, विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपए में)	उद्देश्य
2004	1024.77	इक्विटी निवेश (इन्फ्यूजन) के लिए 200 करोड़ रुपए। बीटीएस विनिर्माण, सीडीएमए, एसएसटीपी, सिम कार्ड और एसडीएच के लिए कैपेक्स निवेश (इन्फ्यूजन) हेतु 150 करोड़ रुपए। वीआरएस के लिए 558 करोड़ रुपए। पुराने पीएफ बकाये के भुगतान के लिए 116.77 करोड़ रुपए।
2009	3000	सभी ऋणों, पीएफ और ग्रेच्युटी की बकाया राशि के शोधन के लिए 2820 करोड़ रुपए। कार्यशील पूंजी के लिए ₹ 180 करोड़ रुपए।
2014	4156.79	देनदारियों के शोधन के लिए पूंजी निवेश और वित्तीय सहायता।

70. विभाग ने आईटीआई पुनरुद्धार योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई सहायता के संबंध में निम्नवत विवरण प्रस्तुत किया:

सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता	राजस्व	पूंजी	कुल (करोड़ रुपए में)
	1892.79	2264	4156.79
वर्षवार प्राप्त सहायता			
2010-11	125.00	-	125.00
2012-13	130.00	-	130.00
2014-15	165.00	192.00	357.00
2015-16	494.02	-	494.02
2016-17	500.00	80.00	580.00
2016-17 (सरकारी गारंटी शुल्क में छूट)	45.79	-	45.79
2017-18	132.98	337.00	469.98
2018-19	-	55.00	55.00
2019-20	300.00	105.00	405.00
2020-21		105.00	105.00
2021-22		71.56	71.56
2022-23	-	80.00	80.00
कुल	1,892.79	1,025.56	2,918.35

वर्ष 2020-21 में उपरोक्त 4156.79 करोड़ रुपये की सहायता के अलावा सांविधिक बकायों के लिए 299.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत राशि स्वीकृत की गई, जिसमें से वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान 120.40 करोड़ रुपये जारी किए गए। शेष 179.29 करोड़ रुपये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

सरकार से अभी भी अपेक्षित सहायता निम्नवत है:

- i. **कैपेक्स:** जैसा कि ऊपर वर्णित है, आईटीआई को 2014 की पुनरुद्धार योजना में कैपेक्स की स्वीकृत राशि का केवल 45.29% अंश विभिन्न चरणों (स्टैगर्ड) में दिया गया है। शेष राशि शीघ्र जारी करने से पुनरुद्धार योजना को पूर्णतया कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी।
- ii. **वैधानिक देनदारियां:** पुनरुद्धार योजना में अतिदेय वैधानिक देनदारियों के लिए 360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और फरवरी 2014 के दौरान पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित किया गया था। हालांकि, कंपनी को फरवरी 2016 के महीने से शुरू होकर विभिन्न चरणों (स्टैगर्ड) में 360 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था और इसकी अंतिम किस्त मार्च 2018 के दौरान जारी की गई थी। परिणामस्वरूप, दिनांक 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार बकाया वैधानिक देनदारियों में 299.69 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। वर्ष 2020-21 में वैधानिक देनदारियों की मद में 299.69 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राहत (गैर योजना-राजस्व) का अनुमोदन प्राप्त हुआ, जिसमें से वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के दौरान 120.40 करोड़ रुपये जारी किए गए। शेष 179.29 करोड़ रुपये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस राशि के जारी होने से आईटीआई को कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित वैधानिक बकाये का भुगतान करने में मदद मिल सकेगी।”

71. विभाग से आईटीआई लिमिटेड द्वारा किए गए व्यय का विवरण और आईटीआई लिमिटेड द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन की दिशा में विभाग द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया तो विभाग ने निम्नवत बताया:

“आज तक 2264 करोड़ रुपये के कैपेक्स अनुदान में से आईटीआई को 1025.56 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। कैपेक्स निधियों का निवेश दूरसंचार उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन संयंत्रों में एसएमटी (सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी) लाइन्स, डेटा सेंटर, पीसीबी (प्रिंटेड सर्किट बोर्ड) विनिर्माण, 3डी प्रिंटिंग सेवाओं, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशालाओं, पंच प्रेस जैसे मैकेनिकल इंफ्रा,

इंजेक्शन मोल्डिंग जैसे विनिर्माण अवसंरचना के उन्नयन के लिए किया गया है। विभिन्न इकाइयों में किए जा रहे विनिर्माण अवसंरचना और उत्पादों/सेवाओं के इकाई-वार उन्नयन का विवरण अनुबंध-V में दिया गया है।

उन्नत विनिर्माण अवसंरचना के साथ, कंपनी ने सभी निविदाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और परियोजनाओं के निष्पादन का पूर्ण स्वामित्व लेने के लिए अपनी रणनीति को भी बदल दी। परिणामस्वरूप, कंपनी ने कई नई परियोजनाओं को हासिल किया और कुछ परियोजनाएं चल रही हैं।

क) भारतनेट चरण I:

ख) भारतनेट चरण II:

(i) गुजरात (गुजनेट)

(ii) महाराष्ट्र (महानेट)

(iii) अंडमान और निकोबार परियोजना

(iv) टैन्फीनेट परियोजना।

ग) आर्मी स्टेटिक स्विचड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एएससीओएन) चरण-IV परियोजना।

घ) 4जी टीसीएस प्रौद्योगिकी आरएएन विनिर्माण।

ड) 4जी सीडीओटी प्रौद्योगिकी आरएएन विनिर्माण।

विभिन्न उत्पादों/सेवाओं के लिए आवंटित कैपेक्स का उपयोग करके सृजित व्यवसाय 'नीचे दर्शाए अनुसार:

मद विवरण	मूल्य करोड़ रुपये में
कुल प्राप्त कैपेक्स	1025.56
बिजनेस जनरटेड (प्राप्त हुए कस्टमर ऑर्डर)	2175.59
उपलब्ध टर्न ओवर	1878.03
निष्पादन के तहत शेष आदेश	297.60

उत्पादों का विपणन:

आईटीआई द्वारा उत्पादों के विवरण के संबंध में विभाग द्वारा निम्नलिखित जानकारी दी गई :

1. आईटीआई पूरे भारत में विभिन्न विपणन कार्यालयों के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंच रहा है। आईटीआई अधिकारी संभावित ग्राहकों से मिलते हैं और निविदाओं में भाग लेते हैं।
2. आईटीआई ने आईटीआई उत्पादों के व्यापक प्रचार के लिए एस्पारिंग हरियाणा 2022, चेन्नई में लीडरशिप फॉर बिजनेस एक्सीलेंस एंड इनोवेशन 2022 पर 31 वीं विश्व कांग्रेस, बंगलूर में टेक समिट 2022, दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस (आईएमसी 2022), हरित ऊर्जा क्रांति सम्मेलन 2022 नई दिल्ली में, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 लखनऊ, ताज होटल में उत्पाद प्रदर्शन, बंगलूर में जनवरी-2023 में लोक सभा की स्थायी समिति के दौरे के दौरान, बंगलूर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023, बंगलूर में एयरो इंडिया 2023 आदि जैसी प्रदर्शनियों में भाग लिया था।
3. आईटीआई नियमित पत्राचार और सोशल मीडिया द्वारा भी पहुंच रहा है।
4. आईटीआई ने सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, सीपीएसयू के सीएमडी डाक विभाग, बैंकों आदि को पत्राचार किया है। ”

आईटीआई लिमिटेड का विनिवेश

72. समिति द्वारा आईटीआई लिमिटेड के विनिवेश के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर निम्नवत बताया गया:

“डीआईपीएम ने दिनांक 04-02-2021 को अपने ओएम संख्या 3/3/2020-डीआईपीएम-II-बी (ई) के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (“पीएसई”) नीति जारी की है। नीति में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार डीआईपीएम को नीति आयोग और विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी) की सिफारिश के आधार पर रणनीतिक क्षेत्रों में विशिष्ट सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश से संबंधित मामलों को प्रोसेस करना है। इन सिफारिशों के आधार पर यदि रणनीतिक क्षेत्र के विशेष सीपीएसई को सरकारी नियंत्रण के तहत रखा जाता है या अन्यथा विचार करते हैं तो वैकल्पिक तंत्र (एएम) इसका अनुमोदन करेगा। इस नीति ने दूरसंचार को अन्यो के बीच रणनीतिक क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। उपरोक्त ढांचे के तहत, नीति आयोग ने दिनांक 05-04-

2021 को अपनी बैठक में आईटीआई लिमिटेड को रणनीतिक विनिवेश के लिए सिफारिशें दीं थीं। इसके बाद विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप (सीजीडी) की बैठक दिनांक 24 जून, 2021 को आयोजित की गई थी। सीजीडी ने निम्नवत सिफारिश की है:

वैकल्पिक तंत्र (एएम) से आईटीआई लिमिटेड के संबंध में सीजीडी की सिफारिशों पर विचार करने का अनुरोध किया जा सकता है कि इसे अपने क्षेत्र के भीतर न्यूनतम सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में बनाए नहीं रखा जा सकता है।

वैकल्पिक तंत्र (एएम) से आईटीआई लिमिटेड के निजीकरण के संबंध में सीजीडी की सिफारिशों पर विचार करने का भी अनुरोध किया जा सकता है और यदि अनुमोदित किया जाता है तो डीआईपीएएम नई पीएसई नीति के अनुसार सीसीईए के "सैद्धांतिक" अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामले की प्रोसेस कर सकता है।

इसके बाद, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने उर्वरक विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, आवासन और शहरीकार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और दूरसंचार विभागके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सीपीएसई के संबंध में "गैर-रणनीतिक क्षेत्र में निजीकरण या बंद करने के लिए सीपीएसई की पहचान" के लिए 12 अगस्त, 2022 को नीति आयोग के सीईओ की अध्यक्षता में अधिकारियों के समूह (सीजीओ) की एक बैठक बुलाई। समिति ने निर्णय लिया कि आईटीआई लिमिटेड को इसके अलग होने के बाद रणनीतिक विनिवेश के लिए लिया जाना चाहिए। इसके बाद दूरसंचार विभाग ने दिनांक 05.09.2022 के पत्र के माध्यम से डीआईपीएएम से वैकल्पिक तंत्र (एएम) के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। वर्तमान में यह मामला डीआईपीएएम के विचाराधीन है।

भारतनेट चरण-I और चरण-II के बीच तुलना

क्र. सं.	मद	चरण-I	चरण -II
1	ग्राम पंचायतों की संख्या	1,00,000 (दिनांक 30.04.2017 को दूरसंचार आयोग द्वारा कार्य क्षेत्र को बढ़ाकर लगभग 1,25,000 ग्राम पंचायत कर दिया गया)	1,50,000
2	कार्यान्वयन एजेंसियां	तीन सीपीएसयू (बीएसएनएल, रेलटेल और पीजीसीआईएल)	बीबीएनएल/बीएसएनएल, राज्यों और राज्यों की एजेंसियां, सीपीएसयू और निजी क्षेत्र
3	मिडिया	भूमिगत ओएफसी	भूमिगत ओएफसी, मौजूदा बिजली के खंभों पर एरियल ओएफसी और रेडियो और सैटेलाइट
4	नेटवर्क में प्रयुक्त फाइबर	एफपीओआई तक बीएसएनएल फाइबर और उसके बाद नई ओएफसी	ब्लॉक से जीपी तक नई ओएफसी
5	फाइबर की संख्या (कोर)	24	48 और ऊपर (भूमिगत), 24 और ऊपर (एरियल)
6	अंतिम छोर का आर्किटेक्चर	परिकल्पित नहीं	हां, सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए, वाई-फाई हॉटस्पॉट या कोई अन्य उपयुक्त ब्रॉडबैंड तकनीक
7	नेटवर्क प्रौद्योगिकी	जीपीओएन लिनीअर आर्किटेक्चर	आईपी एमपीएलएस/रिंग पर छत्तीसगढ़ को छोड़कर जीपीओएन रैखिक आर्किटेक्चर, राज्य आधारित मॉडल के तहत राज्यों को अपने स्वयं की निधि का उपयोग करके उन्नत आर्किटेक्चर का लचीलापन दिया गया।

चरण-II के कार्यान्वयन की प्रगति निम्नानुसार है:

- **राज्य आधारित मॉडल:** इस मॉडल के तहत 8 राज्यों को कार्यान्वित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ओडिशा झारखंड और गुजरात में काम लगभग पूरा हो चुका है जबकि अन्य राज्यों में कार्यान्वयन का काम प्रगति पर है।

- **बीबीएनएल/बीएसएनएल आधारित निजी मॉडल:** दो राज्यों अर्थात् पंजाब और बिहार को सीधे बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा निजी क्षेत्र के मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। दोनों राज्यों में काम लगभग पूरा हो चुका है।
- **सीपीएसयू:** इस मॉडल के तहत, बीएसएनएल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में काम कर रहा है जहां कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- **उपग्रह:** 5165 ग्राम पंचायतों पर चरण-II के उपग्रह घटक को बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

चरण-II का कार्य कार्यान्वयन के अधीन है और विवरण इस प्रकार हैं:

तालिका: भारतनेट चरण-II परियोजना की स्थिति (दिनांक 09.01.2023 की स्थिति के अनुसार)

कार्यान्वयन मॉडल	नियोजित पंचायतें	ग्राम बिछाई गई (किमी)	ओएफसी सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार ग्राम पंचायतें
राज्य के नेतृत्व वाला मॉडल	65,555	2,04,448	37971
बीएसएनएल	24,334	74,544	17792
निजी एलईडी मॉडल	7,382	22,830	7,358
उपग्रह	5,166	0	4503
कुल	102,437	3,01,822	67,624

अनुबंध - दो

क्र.सं.	कार्रवाई के बिंदु	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य	स्थिति	कमी का कारण
1	भारतनेट: संचयी जीपी जुड़ी हुई हैं	205000	187096	मार्च, 2023 तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना है
2	भारतनेट: डिजिटल राजमार्ग की लंबाई	650000 किमी	611036 किमी	मार्च, 2023 तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना है
3	भारतनेट: सेवा प्रदान करने के लिए तैयार जीपी	205000	187096	मार्च 2023 तक लक्ष्य पूरा होने की संभावना है
4	भारत नेट: सभी राज्यों के सभी गांवों तक फाइबर	6.44 लाख	187096	वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है
5	भारतनेट: पीपीपी मॉडल के तहत जुड़े गांवों की संख्या	00	0	दिनांक 20.07.2021 को जारी आरएफपी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। संशोधित लागत आकलन और कार्यान्वयन संबंधी कार्यनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है
6	प्रत्येक नागरिक के लिए कनेक्टिविटी: भारत में 4 जी फूटप्रिंट का प्रतिशत	99%	98.50%	ग्रामीण और दूरदराज के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुख्य मुद्दा है।
7	5G रोल-आउट: भारत में 5G पर मोबाइल नेटवर्क संबंधी प्रसार का प्रतिशत	प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र (LSA) में 5G सेवाओं का शुभारंभ	दिनांक 27.01.2023 की स्थिति के अनुसार 240 जिलों में फैले प्रत्येक एलएसए में 5जी सेवाएं उपलब्ध हैं।	कोई कमी नहीं।

क्र.सं.	कार्रवाई के बिंदु	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य	स्थिति	कमी का कारण
8	ग्रामीण विकास संस्थानों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: जीपी में प्रदान किए गए एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या	350000	2,07,222	सीएससी द्वारा पहले प्रदान किए गए अधिकांश ब्रॉडबैंड कनेक्शन सीएससी के साथ समझौते की समाप्ति के कारण काट दिए गए थे। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर उद्यमी योजना के माध्यम से प्रदान किए जा रहे हैं। वर्ष 2023 तक मामूली कमी होने की संभावना है
9	आकांक्षी जिलों में कनेक्टिविटी: आकांक्षी जिलों में जुड़े प्रतिशत जीपी (संचयी)	70%	73.13%	लागू नहीं
10	एलडब्ल्यूई मोबाइल कनेक्टिविटी: वामपंथी उग्रवाद प्रभावितक्षेत्रों (एलडब्ल्यूईचरण-II) में संचयी टावर स्थापित किए गए हैं।	2000	284	ग्रामीण और दूरदराज के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुख्य मुद्दा है।
11	मोबाइल कनेक्टिविटी: सेवा से वंचित गांवों के लिए दूरसंचार कवरेज (जुड़े गांवों की संख्या)	4785	1448	ग्रामीण और दूरदराज के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुख्य मुद्दा है।
12	ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट: गांवों में सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की	110000	1,04,664	ग्रामीण और दूरदराज के गांवों में वाईफाई कनेक्टिविटी प्रदान करने

क्र.सं.	कार्रवाई के बिंदु	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य	स्थिति	कमी का कारण
	संचयी संख्या (प्रति जीपी 1 हॉटस्पॉट के साथ)			के लिए निजी दूरसंचार कंपनियों के लिए वाणिज्यिक व्यवहार्यता मुख्य मुद्दा है।
13	पीएम वाणी: पीएम वाणी आधारित ब्रॉडबैंड एक्सेस प्वाइंट का प्रसार (लाखों में संख्या)	130375	136918	
14	लाख किलोमीटर (संचयी) में बिछाई गई ओएफसी की लंबाई	36 लाख किलोमीटर	36.30 लाख किलोमीटर	लागू नहीं
15	फाइबरयुक्त दूरसंचार टावरों का प्रतिशत	55%	36.79%	पुनःवाणिज्यिक व्यवहार्यता और आरओडब्ल्यू अनुमति मुद्दे ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए नए ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की गति को प्रभावित करते हैं।
16	टावरों की संचयी संख्या	10 लाख	7.43 लाख	वाणिज्यिक व्यवहार्यता और आरओडब्ल्यू अनुमति मुद्दे नए मोबाइल टावर स्थापित करने की गति को प्रभावित करते हैं
17	BISAG-N के माध्यम से दूरसंचार के लिए फाइबर मैपिंग	पीएसयू के लिए 100%	76%	लागू नहीं
18	ब्रॉडबैंड स्पीड (एमबीपीएस) की उपलब्धता'	25 एमबीपीएस	18.26 एमबीपीएस	वाणिज्यिक व्यवहार्यता और

क्र.सं.	कार्रवाई के बिंदु	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य	स्थिति	कमी का कारण
				ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए आरओडब्ल्यू अनुमतियों और बहाली शुल्क आदि के लिए उच्च प्रभारों के कारण नए मोबाइल टावर स्थापित करने और ऑप्टिकल फाइबर जो उच्च ब्रॉडबैंड गति के लिए आवश्यक है बिछाने की गति प्रभावित होती है

अनुबंध - तीन

पीएम-वाणी केंद्रीय रजिस्ट्री									
(₹ करोड़ में)									
कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/प्रदेय	वर्तमान स्थिति	स्कीम की कुल लागत	सी-डॉट को आवंटित धनराशि (दिनांक 23 जनवरी तक)	परियोजना पूर्ण होने की तिथि	बजट अनुमान (बीई) वित्त वर्ष 2023-24 (अनंतिम)	वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित परिणाम (अनंतिम)	पीडीओ का विवरण	पीएलआई विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पीएम-वाणी के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री	1. पीएम-वाणी सेंट्रल रजिस्ट्री का डिजाइन, विकास और रखरखाव: -सीआर में केपीआई डैशबोर्ड प्रदान करना, पीएम-वाणी स्कीम का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या और उपयोगकर्ताओं द्वारा उपभोग की जानकारी उपलब्ध करना - पीएम-वाणी पोर्टल का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करना - एलएसए को पीडीओ और पीडीओए पुस्तिका उपलब्ध करना - मेप में	<ul style="list-style-type: none"> दिनांक 9 दिसंबर 2020 को पीएम-वाणी स्कीम को मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद केंद्रीय रजिस्ट्री की पहली रिलीज (रिलीज 1.1) दिनांक 5 जनवरी 2021 को स्थापित की गई है और दिनांक 10 जनवरी 2021 से पीएम-वाणी स्कीम संचालन में है। पीएम-वाणी सीआर (सेंट्रल रजिस्ट्री) 17 क्षेत्रीय भाषाओं में सक्षम है। बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्क के साथ-साथ रेलटेल नेटवर्क का 	24.79	20.21	दिसम्बर -23	4.58	<ul style="list-style-type: none"> पीएम-वाणी ढांचे में रोमिंग कार्य क्षमता के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री का विस्तार। 	<ul style="list-style-type: none"> वर्तमान में 152 पीडीओए से 144816 पीडीओ संचालन में हैं। 152 में से लगभग 105 पीडीओए सी-डॉट स्टैक द्वारा संचालित हैं। 	शून्य

	<p>पीएम-वाणी स्कीम के तहत स्थापित किए गए एक्सेस पॉइंट दिखाना।</p> <p>2. पीडीओए और ऐप प्रदाता के सिस्टम और सॉफ्टवेयर को सत्यापित करना</p> <p>-पीडीओए और ऐप प्रदाता को सत्यापित करने के लिए परीक्षण योजना तैयार जाना है।</p> <p>- सत्यापित अवसंरचना स्थापित किया जाना है।</p> <p>-अनंतिम रूप से सत्यापित पीडीओए और ऐप का पूर्व सत्यापन किया जाना है।</p>	<p>बीएसएनएल/रेलटेल के लिए विकसित वाणी टोकन हैंडलर सॉफ्टवेयर की संस्थापना के साथ पीएम-वाणी में अंतरण हो गया है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50+ पीडीओए और 31 ऐप प्रदाता पूरी तरह से सत्यापित किए जा चुके हैं। • पीडीओए - पीओसी के बीच रोमिंग का उन्नति और परीक्षण नवंबर-2022 में पूरा हो चुका है। रोमिंग संवर्द्धन परामर्श पत्र के साथ वाणी ढांचा (वी3.0) डीओटी को प्रस्तुत किया जा चुका है। 							
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

अनुबंध - चार

क्र.सं.	राज्य	संपत्ति का पता	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	मुद्रीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी
1	आंध्र प्रदेश	टीई, कौंडापल्ली, आंध्र प्रदेश	6,000.00	मंत्री समूह
2	आंध्र प्रदेश	स्टोर यार्ड, ताडेपल्लीगुडेम, आंध्र प्रदेश	10,319.00	मंत्री समूह
3	आंध्र प्रदेश	रिक्त भूमि , एस. अन्नावरम, तुनी, आंध्र प्रदेश	6,377.00	मंत्री समूह
4	आंध्र प्रदेश	रिक्त भूमि , अदोनी, कुरनूल, आंध्र प्रदेश	33,145.00	मंत्री समूह
5	आंध्र प्रदेश	स्टोर यार्ड कंपाउंड, पालाकोले, आंध्र प्रदेश	4,180.00	मंत्री समूह
6	छत्तीसगढ़	एमडबल्यू कंपाउंड, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़	2,180.00	बीएसएनएल
7	गुजरात	बीटीएस, कानबिवागा, भरुच	5,200.00	मंत्री समूह
8	गुजरात	रिक्त भूमि , करीमाबाद, सूरत	5,359.00	मंत्री समूह
9	गुजरात	स्टाफ कॉलोनी, रानीप, अहमदाबाद	4,865.00	मंत्री समूह
10	गुजरात	टेलीफोन एक्सचेंज, मोरबी, गुजरात	2,832.00	मंत्री समूह
11	गुजरात	टेलीफोन एक्सचेंज, मार्केटिंग यार्ड, राजकोट	12,663.00	मंत्री समूह
12	गुजरात	बीएसएनएल स्टाफ क्वार्टर, भावनगर, गुजरात	22636	मंत्री समूह
13	गुजरात	टेलीफोन एक्सचेंज, मिर्जापुर, अहमदाबाद	563.00	बीएसएनएल
14	हिमाचल प्रदेश	प्लॉट सं.20जी, सेक्टर-1ए, परवाणू, हिमाचल प्रदेश	2,900.00	बीएसएनएल
15	कर्नाटक	स्टोर डिपो-II, मगदी मेन रोड, बेंगलुरु	7,500.00	मंत्री समूह
16	कर्नाटक	स्टोर यार्ड, कादरी हिल्स, मैंगलोर	8,094.00	मंत्री समूह
17	केरल	प्रशिक्षण केंद्र, तिरुवनंतपुरम	37328	एनएलएमसी
18	केरल	टीई, चोंडी, अलुवा, एर्नाकुलम, केरल	9,000.00	मंत्री समूह
19	केरल	रिक्त भूमि , कोट्टाराकरा, कोल्लम, केरल	3,580.00	बीएसएनएल
20	केरल	एसक्यू कंपाउंड, चालकुडी, त्रिशूर	4,477.00	बीएसएनएल

21	केरल	एमडबल्यू स्टाफ क्वार्टर, कोडुंगल्लूर, त्रिशूर	1,820.00	बीएसएनएल
22	केरल	रिक्त भूमि , विथुरा, मार्केट जंक्शन, तिरुवनंतपुरम	2,023.35	बीएसएनएल
23	महाराष्ट्र	बीएसएनएल स्टाफ क्वार्टर अंधेरी ईस्ट मुंबई	3486.17	एनएलएमसी
24	महाराष्ट्र	सांता क्रूज, मुंबई	11807	एनएलएमसी
25	महाराष्ट्र	बोरीवली, मुंबई	171718	एनएलएमसी
26	महाराष्ट्र	टीएफ टाउनशिप, देवनार, मुंबई	184059	एनएलएमसी
27	महाराष्ट्र	सीटीओ बिल्डिंग, सिविल लाइंस, नागपुर	18827	एनएलएमसी
28	महाराष्ट्र	स्टाफ क्वार्टर, जेल रोड, नासिक	23347.6	एनएलएमसी
29	मध्य प्रदेश	टेलीकॉम फैक्ट्री में प्लॉट, रानीताल गरहा रोड, जबलपुर	20250	एनएलएमसी
30	मध्य प्रदेश	टेलीकॉम फैक्ट्री में प्लॉट, स्नेहनगर रोड, जबलपुर	20085	एनएलएमसी
31	मध्य प्रदेश	50 प्लॉट, कालानी बाग, देवास	12,172.00	मंत्री समूह
32	मध्य प्रदेश	संचार विकास भवन, सिविल लाइंस, जबलपुर	5,462.00	मंत्री समूह
33	मध्य प्रदेश	कृषि उपज मंडी में 26 प्लॉट, विजय नगर, जबलपुर	5,686.00	मंत्री समूह
34	मध्य प्रदेश	टीई, राजेंद्र टॉकीज, शहडोल, मध्य प्रदेश	2,683.65	बीएसएनएल
35	मध्य प्रदेश	स्टाफ क्वार्टर कंपाउंड, दम दम रोड, संखेड़ा नाका, पुरानी इटारसी, मध्य प्रदेश	9,710.00	बीएसएनएल
36	मध्य प्रदेश	ए-65, एम/डबल्यू कंपाउंड, ए.बी. रोड, कालानी बाग, देवास सिटी, मध्य प्रदेश	651.00	बीएसएनएल
37	मध्य प्रदेश	स्टाफ क्वार्टर कंपाउंड, प्लॉट सं. ए165 से 174, ईएसआई के पास, कालानी बाग, देवास सिटी, मध्य प्रदेश	2,142.00	बीएसएनएल
38	मध्य प्रदेश	स्टाफ कॉलोनी, खातीवाला टैंक, इंदौर	1,185.00	बीएसएनएल
39	पुदुचेरी	कोएक्सियल कंपाउंड कोलास नगर, पुदुचेरी	2,237.00	मंत्री समूह
40	पंजाब	आरटीटीसी, राजपुरा, पंजाब	79537	मंत्री समूह

41	पंजाब	एससीओ 143, 144 एफएफ, छोटी बारादरी, पटियाला	778.00	बीएसएनएल
42	तमिलनाडु	कल्लिकुप्पम, अंबतूर, चेन्नई	24400	एनएलएमसी
43	तमिलनाडु	व्यास नगर, चेन्नई	120283	एनएलएमसी
44	तमिलनाडु	स्टाफ क्वार्टर, रोयापेट्टा, चेन्नई	21181	एनएलएमसी
45	तमिलनाडु	टेलीफोन हाउस, एनएससी बोस रोड, चेन्नई	4047	एनएलएमसी
46	तमिलनाडु	वायरलेस स्टेशन, एननोर, चेन्नई	124531	एनएलएमसी
47	तमिलनाडु	टीई, दिनरोस, चेन्नई	4,047.00	मंत्री समूह
48	तमिलनाडु	मेगावाट स्टेशन, चेंगलपट्टूर, तमिलनाडु	29,097.00	मंत्री समूह
49	तमिलनाडु	गोदाम और स्टाफ क्वार्टर, गणपति, कोयंबटूर	6,394.00	मंत्री समूह
50	तमिलनाडु	टेलीफोन एक्सचेंज, उदुमलपेट, तमिलनाडु	4,267.00	मंत्री समूह
51	तमिलनाडु	माइक्रोवेव स्टेशन, मेट्टुपलयम, कोयंबटूर	2,929.00	मंत्री समूह
52	तमिलनाडु	डीटीओ, विल्लुपुरम, तमिलनाडु	2,396.00	मंत्री समूह
53	तमिलनाडु	टेलीफोन एक्सचेंज, सुलूर, तमिलनाडु	1,990.00	बीएसएनएल
54	तेलंगाना	आरटीटीसी, गाचीबोवली, हैदराबाद	155180	एनएलएमसी
55	तेलंगाना	स्टाफ क्वार्टर, मालकपेट, हैदराबाद	3,014.00	मंत्री समूह
56	तेलंगाना	टेलीफोन एक्सचेंज परिसर, पटनाचेरु, तेलंगाना	3,000.00	बीएसएनएल
57	उत्तर प्रदेश	टेलीकॉम कंपाउंड, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ	30484	एनएलएमसी
58	उत्तर प्रदेश	एस/क्यू, सेक्टर-जी, एलडीए कॉलोनी, लखनऊ	11,792.20	मंत्री समूह
59	उत्तर प्रदेश	एस/क्यू, विकास नगर, लखनऊ	9,227.00	मंत्री समूह
60	उत्तर प्रदेश	स्टोर, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ	4,806.00	मंत्री समूह
61	उत्तर प्रदेश	टीई, रामपुर बनवारी, बिजनौर	3,800.00	मंत्री समूह
62	उत्तर प्रदेश	स्टाफ क्वार्टर, सुहाग नगर फिरोजाबाद	4,750.00	मंत्री समूह
63	उत्तर प्रदेश	सराय बीका, जौनपुर	3,800.00	बीएसएनएल

64	उत्तर प्रदेश	करियां, मछलीशहर, जौनपुर	2,750.00	बीएसएनएल
65	उत्तर प्रदेश	बेलवाड़, जौनपुर	2,430.00	बीएसएनएल
66	उत्तर प्रदेश	बधवा बाजार, मछलीशहर, जौनपुर	2,950.00	बीएसएनएल
67	उत्तर प्रदेश	रिक्त भूमि , लेडूका गांव, जौनपुर	2,180.00	बीएसएनएल
68	पश्चिम बंगाल	टीएफ, गोपालपुर	182675	एनएलएमसी
69	पश्चिम बंगाल	मध्यमग्राम, कोलकाता	44663	एनएलएमसी
70	पश्चिम बंगाल	ओल्ड टी. ई. बिल्डिंग, बैरकपुर, कोलकाता	2,711.39	मंत्री समूह

अनुबंध - पांच

क्र. सं.	इकाई	शुरू किए जा रहे उत्पाद/सेवाएं	उन्नत विनिर्माण अवसंरचना
1	बंगलोर	एन्क्रिप्शन उत्पाद, वाई-फाई एक्सेस उत्पाद, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला सेवाएं, डेटा सेंटर, हाई-डेंसिटी पॉलीथीन (एचडीपीई)	एसएमटी लाइन्स, मैकेनिकल इंप्रा, इंजेक्शन मोल्डिंग, पीसीबी प्लांट अपग्रेडेशन, 3डी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस (ईएमआई)/इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्पैटिबिलिटी (ईएमसी) लैब, सेफ्टी लैब, एचडीपीई मैनुफैक्चरिंग लाइन, आर एंड डी इंप्रा का अपग्रेडेशन, डेटा सेंटर के लिए इंप्रास्ट्रक्चर
2	रायबरेली	गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क (जीपीओएन) - ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल (ओएलटी) और ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल, उपकरण (ओएनटी), ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी), हाई-डेंसिटी पॉलीथीन (एचडीपीई) डक्ट, स्विच मोड पावर सप्लाई (एसएमपीएस)	एसएमटी लाइन्स, एचडीपीई और ओएफसी मैनुफैक्चरिंग लाइन्स, एसएमपीएस के लिए परीक्षण उपकरण
3	पालक्कड़	स्मार्ट कार्ड, कॉम्पोनेंट स्क्रीनिंग, माइक्रो पीसी, स्मार्ट एनर्जी मीटर, एचडीपीई डक्ट, लैपटॉप	एसएमटी लाइन्स, पीसीबी प्लांट अपग्रेडेशन, स्मार्ट कार्ड मैनुफैक्चरिंग सुविधा, एचडीपीई मैनुफैक्चरिंग लाइन, कॉम्पोनेंट स्क्रीनिंग के लिए एनवॉयर्नमेंटल चैंबर और परीक्षण जिग
4	नैनी यूनिट	सौर पैनल	सौर पैनल मैनुफैक्चरिंग लाइन
5	मनकापुर यूनिट	जीपीओएन-ओएनटी, एचडीपीई, फडीएमएस	एसएमटी लाइन्स, जीपीओएन ओएनटी के लिए टेस्ट सेटअप, एचडीपीई मैनुफैक्चरिंग लाइन

भाग-दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

दूरसंचार विभाग का बजट

वार्षिक बजट की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटन की मांग करते हुए मांग सं. 13 को 08.02.2023 को लोक सभा के पटल पर रखा। विभाग से संबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने अपने अधिदेश के अनुसार दूरसंचार विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगें 2023-24 की सविस्तार जांच की और कतिपय टिप्पणियां/सिफारिशें की जो निम्नवत पैरा में सविस्तार दी गई हैं:

2023-24 के दौरान बजटीय आवंटन और उपयोग

1. समिति नोट करती है कि दूरसंचार विभाग ने विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें 08.02.2023 को सभा पटल पर रखीं जो कुल 108153.25 करोड़ रुपए की हैं। समिति नोट करती है कि 2022-23 के लिए बजट अनुमान 95547.80 करोड़ रुपए था जिसे संशोधित अनुमान 2022-23 में घटाकर 84903.69 करोड़ रुपए कर दिया गया, जबकि दिसम्बर 2022 में वास्तविक व्यय 57666.02 करोड़ रुपए रहा है जो 67.91 प्रतिशत निधि उपयोग दर्शाता है और इससे पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतिम दो महीनों में उपयोग के लिए 32.09 प्रतिशत आवंटन बचा हुआ है। समिति मंत्रालय से आग्रह करती है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी व्यय नियंत्रण दिशानिर्देशों का ईमानदारी से अनुपालन करे और निर्धारित निधियों का उपयुक्त तरीके से उपयोग करे। समिति को विश्वास है कि मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक शेष निधियों का उपयोग करने के लिए सभी विवेकसम्मत उपाय करेगा।

2. समिति नोट करती है कि विभाग ने 2023-24 के लिए 84996.98 करोड़ रुपए के कुल अनुदान का प्रस्ताव किया था जबकि बजट अनुमान 2023-24 में कुल आवंटन में 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। निधि आवंटन में की गई महत्वपूर्ण वृद्धि की प्रशंसा करते हुए समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह अपनी शुरु की गई महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं में तेजी लाए। इस तथ्य के आलोक में कि विभाग के विभिन्न योजनाओं का प्रभावी और सुगम कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान बढ़े हुए आवंटन का पूरा उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। समिति चाहती है कि सिफारिश के अनुपालन में किए गए उपायों से उसे अवगत कराया जाए।

3. बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत 108153.25 करोड़ रुपए के कुल आवंटन में से राजस्व खंड के अंतर्गत 41461.43 करोड़ रुपए और पूंजी खंड के अंतर्गत 66691.82 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2022-23 किए गए बजट अनुमान आवंटन से यह धनराशि 12605.45 करोड़ रुपए अधिक है। पिछले वर्ष से तुलना करने पर राजस्व खंड में यह वृद्धि 9025.05 करोड़ रुपए है और पूंजी खंड में यह वृद्धि 3508.4 करोड़ रुपए है। राजस्व खंड में यह वृद्धि यूएसओएफ के लिए सेवा प्रदाता को क्षतपूर्ति, 4जी स्पेक्ट्रम में जीएसटी का अनुदान और बीएसएनएल को संभाव्यता अंतर वित्तपोषण के कारण से है। पूंजी खंड में वृद्धि मुख्यतः 'बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पूंजी निवेश' शीर्ष के अंतर्गत है। समिति नोट करती है कि तीन योजनाएं नामतः टीडीटीपी (टेक्नॉलोजी डेवलेपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन), पीएलआई और चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम 915 करोड़ रुपए की कुल परिच्यय के साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्री इनसैंटिवाइजेशन स्कीम के अंतर्गत लाई गई हैं।

जहां तक उपयोग का संबंध है, समिति नोट करती है कि राजस्व खंड में बजट अनुमान 2022-23 में 32436.38 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 46157.80 करोड़ रुपए किया गया और दिसम्बर 2022 तक वास्तविक व्यय की धनराशि मात्र 24291.31 करोड़ रुपए रही है। यह धनराशि संशोधित अनुमान में किए गए आवंटन का मात्र 52.6 प्रतिशत है। राजस्व खंड में संशोधित अनुमान के अंतर्गत निधि आवंटन में वृद्धि मुख्यतः बीएसएनएल को संभाव्यता अंतर वित्तपोषण और यूएसओएफ आरडी के अंतर्गत है। पूंजी खंड में 2022-23 में बजट अनुमान के अंतर्गत 63111.42 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन हुआ जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 38745.89 करोड़ रुपए किया गया तथा दिसम्बर 2022 में वास्तविक उपयोग मात्र 33374.71 करोड़ रुपए का रहा। निधियों का कम उपयोग कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पूंजी निवेश, आईटीआई रिवाइवल के लिए इक्विटी इन्फ्यूजन, वायरलेस सेटस एंड इक्विपमेंट (टीईसी), टेलीकॉम टेस्टिंग एंड सिम्योरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर (टीटीएससीसी), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेस रिऑग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन (एसटीआर), मैनडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आफ टेलीकॉम इक्विपमेंट (एमटीसीटीई) आदि में देखा गया है।

समिति नोट करती है कि दिसम्बर 2022 की स्थिति के अनुसार संशोधित अनुमान के संदर्भ में 2022-23 के दौरान राजस्व और पूंजी के अंतर्गत निधियों का उपयोग क्रमशः 52.06 प्रतिशत और 86.1 प्रतिशत रहा है। समिति नोट करती है कि राजस्व खंड के अंतर्गत बीएसएनएल को संभाव्यता अंतर वित्तपोषण के अंतर्गत 18127 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान आवंटन के मुकाबले दिसंबर 2022 तक 5 हजार करोड़ रुपए मात्र खर्च किए जा सके। विभाग ने यह आश्वासन दिया है

कि निधि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निधि उपयोग की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे यूएसओएफ (आरडी), चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं, मैनडेटरी टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन आफ टेलीकॉम इक्विपमेंट (एमटीसीटीई) की परिचालन लागत, आदि के अंतर्गत निधियों का निर्धारित से कम उपयोग देखा गया है। समिति नोट करती है कि पूंजी खंड के अंतर्गत 2022-23 के दौरान अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत उपयोग का पैटर्न निर्धारित स्तर के अनुरूप नहीं है जैसे कि रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी नेटवर्क, वायरलेस सेटस एंड इक्विपमेंट (टीईसी), बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए स्वदेशी 5जी टेस्ट बेड पूंजी निवेश, आईटीआई रिवाइवल (इक्विटी इन्फ्यूजन), टेलीकॉम टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन। समिति मंत्रालय से उन योजनाओं पर व्यय करने के तरीके में संतुलन लाने का आग्रह करती है जिनके अंतर्गत उपयोग का प्रतिशत निर्धारित से कम है जिससे 31 मार्च 2023 तक 2022-23 के बजटीय आवंटन की इष्टतम प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। समिति को इस बारे में सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों से अवगत कराया जाए।

सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) - निधि आवंटन और उपयोग

4. समिति नोट करती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अनुसार, लाइसेंस शुल्क जिसके अंतर्गत यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) सम्मिलित है, लाइसेंसधारी से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 5 प्रतिशत की दर से लिया जाता है। इसकी शुरुआत अर्थात् 2002-2003 से 1,34,076.96 करोड़ रुपए यूएएल के रूप में एकत्रित किया गया है और 69,590.89 करोड़ रुपए का उपयोग

किया गया है। 31.12.2022 के अनुसार यूएल में शेष धनराशि जो यूएसओ के अंतर्गत पर्याप्त राशि है व 64486.07 करोड़ रुपए है। समिति को यह भी बताया गया है कि यूएल के अधीन एकत्रित निधि को भारत की समिति निधि में रखा जाता है और यह व्यपगत नहीं होती है। तथापि समिति यह नोट कर व्यथित है कि यूएसओएफ के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में धनराशि आरक्षित है फिर भी विभाग खर्च करने को लेकर बहुत कुछ नहीं कर पाया। वर्ष 2022-23 में 9 हजार करोड़ रुपए बजट अनुमान 2022-23 में आवंटित थे जिसे घटाकर संशोधित अनुमान में 3010 करोड़ रुपए कर दिया गया है और 31.12.2022 तक वास्तविक उपयोग 2067 करोड़ रुपए का हो पाया है। उपर्युक्त के मद्देनजर उपयोग में सुधार करने के लिए रणनीति बनाने पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 के लिए विभाग ने 11400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है और 2022-23 और 2023-24 के लिए 130 करोड़ रुपए का अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत निधि आवंटन सहित बजट अनुमान 2023-24 में 10400 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। समिति यह नोट कर प्रसन्नता व्यक्त करती है कि गत वर्ष की तुलना में 1400 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। समिति अवगत है कि यूएसओएफ के साथ प्राथमिकता वाली अनेक चालू योजनाएं लाइन अप है। जिसमें पूरे भारत में 6 लाख गांवों को ब्राडबैंड कनेक्टिविटी का प्रावधान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन केबल बिछाना और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी सहित द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमा क्षेत्रों के कवर न किए गए गांव में मोबाइल सेवाओं की योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं योजना और वामपंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए योजना सम्मिलित है। इन अत्यंत पूंजी निहित असंरचना परियोजनाओं का समय से एवं प्रभावी कार्यान्वयन से उन क्षेत्रों में दूर संचार कनेक्टिविटी में सुधार

करने में पर्याप्त मदद मिलेगी जो वर्तमान में कवर नहीं है और दुर्गम है। इस बात पर विचार करते हुए कि यूएसओएफ के अंतर्गत भारी शेष पहले से ही संभाव्य निधि के रूप में मौजूद है, समिति इस बात पर बल देती है कि निधियों की उपलब्धता यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। समिति का मत है कि वर्ष-दर-वर्ष संशोधित स्तर पर बजट धनराशि में कमी किया जाना यह दर्शाता है कि विभाग की आयोजना दोषपूर्ण है और इससे बचने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि विभाग वर्ष 2023-24 में यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बजट अनुमान में आवंटित 10,400 करोड़ रुपये के इष्टतम उपयोग के लिए प्रयास करे। समिति को इस मामले में की गई कार्रवाही से अवगत कराया जाए।

भारतनेट के तहत निधि आवंटन और उपयोग

5. समिति ने नोट किया कि 2022-23 के लिए भारतनेट के तहत फंड आवंटन 7,000 करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान में घटाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया गया था। हालांकि, व्यय 31.12.2022 तक 85% यानी 1280 करोड़ रुपये रहा है। इसके अलावा, 2023-24 के लिए बजट अनुमान 5,000 करोड़ रुपये रखा गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान से संशोधित अनुमान में कटौती के कारणों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया था कि यह राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत धीमे कार्यान्वयन और भारतनेट की पीपीपी निविदा में अनुकूल बोली प्राप्त न होने के कारण था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के दौरान, विभाग को 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। समिति का विचार है कि आवंटन उन

अनुमानों पर आधारित हैं जो कि इस भरोसे पर तैयार किए गए हैं कि पाइपलाइन में चल रही परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति होगी और आवंटनों का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, समिति को उम्मीद है कि परियोजनाएं योजना के अनुसार पूरी हो जाएंगी। समिति को इस संबंध में अवगत कराया जाए।

भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

6. समिति नोट करती है कि भारतनेट दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और देश में सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) (लगभग 2.6 लाख) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I दिसंबर, 2017 में 1 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों के कार्यान्वयन के साथ पूरा हुआ था। चरण-II कार्यान्वयनाधीन है। विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच करते हुए, समिति ने नोट किया कि 31 दिसंबर, 2022 तक 36800 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है, 611036 किलोमीटर ओएफसी बिछाया गया है, 187096 जीपी को सेवा प्रदान करने हेतु तैयार कर दिया गया है, 104664 जीपी में वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान किए गए हैं, 207222 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, 58316 किलोमीटर डार्क फाइबर को पट्टे पर दिया गया है आदि। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि 5789 टीबी डेटा खपत भी दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की उम्मीद है। समिति नोट करते हैं कि 65,772 ग्राम पंचायतों पर वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान किए जाने बाकी हैं जो सेवा के लिए तैयार हैं। समिति ने पाया कि 2022-23 के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। इसके कारण यह बताये गये थे कि बीएसएनएल को अपने आंतरिक मुद्दों और वित्तीय स्थिति के कारण क्षमता की कमी का सामना करना पड़ा था और चूंकि कोई अनुकूल बोली प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके लिए वैश्विक निविदा जारी की

गई थी, इसलिए वित्त वर्ष 2022-23 में भारतनेट के पीपीपी मॉडल के लिए कोई व्यय नहीं किया जा सका। विभाग के सामने आ रही बाधाओं को मानते हुए, समिति का विचार है कि योजना की प्रगति में बाधा उत्पन्न करने वाली कमियों को दूर करने की दिशा में अग्रसक्रिय उपाय शुरू किए जाने चाहिए। समिति विभाग पर दबाव बनाना चाहेगी कि वह सेवा के लिए तैयार सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान करने के लिए सभी प्रयास करे।

इसके अलावा, समिति की चर्चा के दौरान उसके समक्ष एक प्रासंगिक मुद्दा ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बीएसएनएल की खराब मोबाइल कनेक्टिविटी से संबंधित था। कई दिनों तक बीएसएनएल के मोबाइल टावरों के कार्य नहीं करने के संबंध में टावर के बैटरी का डाउन होना, डीजल की अनुपलब्धता के कारण जेनरेटर का कार्य नहीं करना, आदि जैसे छोटे कारणों को नोट कर समिति क्षुब्ध है। यह दुर्भाग्य की बात है कि इन मूलभूत कारणों से बीएसएनएल का ग्राहक आधार कम हो रहा है। इसलिए, समिति आशा करती है कि विभाग उसकी चिंताओं को दूर करने के लिए उपयुक्त उन्नत उपाय करेगी।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए कार्यों की जांच

7. समिति नोट करती है कि चरण-1 के तहत लगभग 1.10 लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सेवाओं का प्रावधान सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष कहा कि 5 परियोजनाएं हैं जिनके तहत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड को 4000 करोड़ रुपये का काम दिया गया है, जिसमें रखरखाव, अंतिम मील तक कनेक्टिविटी और वाई-फाई एक्सेस पॉइंट आदि शामिल हैं। समिति आगे नोट करती है कि यूएसओएफ, बीबीएनएल और सीएससी-एसपीवी द्वारा

दिनांक 15-07-2019 को एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, जिसमें शेष भारतनेट चरण-1 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी, राशन की दुकानों, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों, डाकघरों आदि को 1 वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए सीएससी-एसपीवी को वीजीएफ प्रदान किया गया है। समझौते के जनादेश के अनुसार, सीएससी-एसपीवी को 5 साल के लिए सेवा प्रदान करने का काम सौंपा गया था। हालांकि, साक्ष्य के दौरान, यह पता चला कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए सभी वाई-फाई और एफटीटीएच कनेक्शन इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईएलआई) का भुगतान नहीं करने के कारण काट दिए गए हैं। समिति यह जानकर निराश है कि सीएससी के साथ समझौते की समाप्ति के बाद भी आज तक विभाग ने स्पष्ट रूप से उनकी समीक्षा नहीं की है। समिति का विचार है कि सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी संस्थानों को 1 वाई-फाई और 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने में किए गए कार्यों की गहन समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, समिति विभाग से उन सरकारी संस्थानों और ग्राम पंचायतों की वास्तविक संख्या की भी पुष्टि करने का आह्वान करती है जिन्हें इसकी स्थापना के बाद एक वर्ष के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान किया गया था। समिति को लोकसभा में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर स्थापित वाई-फाई/एफटीटीएच कनेक्शनों के भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन की जांच करने के लिए यूएसओएफ के तहत स्थापित तीसरे पक्ष के एजेंसी की रिपोर्ट की प्रगति और परिणाम से भी अवगत कराया जाए।

6 लाख गांवों को जोड़ने के लिए भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति

8. समिति नोट करती है कि 30 जून, 2021 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त, 2023 तक देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति के लिए मंजूरी दे दी थी। भारतनेट को अब सभी 6.4 लाख आबाद गांवों को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। ये 16 राज्य केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। संशोधित कार्यनीति में रियायतग्राही/निजी सेवा प्रदाता द्वारा भारतनेट नेटवर्क का सृजन, उन्नयन, प्रचालन, अनुरक्षण और उपयोग शामिल है, जिनका चयन वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उपरोक्त पीपीपी मॉडल के लिए अनुमोदित अनुमानित अधिकतम व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण 16 राज्यों के लिए 19,041 करोड़ रुपये है। ग्राम पंचायतों सहित अनुमानतः 3.61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। समिति को यह बताया गया है कि 16 राज्यों में पीपीपी मॉडल के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया गया है। हालांकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के कारण, इसे रद्द कर दिया गया है और 2025 तक भारतनेट संतृप्ति के लिए एक संशोधित रणनीति पर अग्रिम चरण में विचार-विमर्श चल रहा है। विभाग द्वारा उद्धृत गैर-अनुकूल बोली के प्रमुख कारणों में राज्यों में कम अनुमानित परियोजना लागत (ईपीसी), ईपीसी के प्रतिशत के रूप में सीमित व्यवहार्यता अंतर निधि, मौजूदा भारतनेट नेटवर्क की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता (दोषपूर्ण/हानिकर फाइबर) पर न्यूनतम दृश्यता, केंद्रीय एजेंसियों से आरओडब्ल्यू प्रभारों में छूट न होना, निकास खंडों पर स्पष्टता की कमी शामिल है। रियायतग्राही से महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता वाले ऐसे बड़े पैकेज जिनमें अनेक राज्य शामिल हों, मौजूदा सेवा प्रदाता की ओएफसी परिसंपत्तियों का लाभ उठाने में सीमित लचीलापन आदि। समिति नोट करती है कि एक संशोधित मॉडल

तैयार किया जा रहा है। तथापि, समिति इस बात को लेकर चिंतित है कि भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति धीमी रही है क्योंकि कार्य काफी हद तक 8 राज्यों (राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल के तहत लगभग 65,000 ग्राम पंचायतों) और बीएसएनएल (सीपीएसयू के नेतृत्व वाले मॉडल में 23000 ग्राम पंचायतों) पर निर्भर है, जहां प्रगति धीमी रही है, राज्यों द्वारा परियोजनाओं का खराब निष्पादन और इसकी अनिश्चित वित्तीय स्थितियों के कारण बीएसएनएल की क्षमता की कमी ने भी चरण-II के तहत प्रगति को प्रभावित किया है। समिति का मानना है कि इस परियोजना में अकथनीय लंबी अवधि का विलम्ब हुआ है और इससे ग्रामीण आबादी का बड़ा हिस्सा अन्यायपूर्ण रूप से ई-सेवाओं और संचार सुविधाओं से वंचित हुआ है। इस प्रकार, परियोजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाने की तत्काल आवश्यकता है क्योंकि लक्ष्य अब सभी बसे हुए गांवों अर्थात् अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए 6 लाख गांव तक बढ़ा दिया गया है, सृजित नेटवर्क के रख-रखाव और नेटवर्क के बढ़ते उपयोग पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समिति 16 राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के कार्यान्वयन में अनकही बाधाओं को ध्यान में रखते हुए यह चाहती है कि 16 राज्यों में पीपीपी के माध्यम से भारतनेट के लिए तैयार किए जा रहे संशोधित मॉडल को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और बिना और विलंब के परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जाए। इस संबंध में विस्तृत प्रगति और उस पर उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।

भारतनेट उद्यमी योजना

9. भारतनेट नेटवर्क के उपयोग के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करके एक लाख एफटीटीएच कनेक्शन शुरू करने के लिए बीएसएनएल के एक प्रायोगिक प्रस्ताव को

यूएसओएफ द्वारा इंटरनेट लीज्ड लाइन (आईआईएल) और पूंजी प्रोत्साहन दोनों के लिए यूएसओएफ से 89 करोड़ रुपये की वित्तीय सब्सिडी के साथ अनुमोदित किया गया है। समिति को सूचित किया गया है कि जनवरी, 2023 के पहले सप्ताह तक 1 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे। अब दिसंबर 2023 तक भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के माध्यम से भारतनेट का उपयोग करके 5 लाख एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रायोगिक विस्तार किया गया है। समिति को यह समझाया गया है कि 13.02.2023 तक, प्रायोगिक परियोजना के तहत बीएसएनएल के साथ राजस्व साझेदारी भागीदार के रूप में 2396 बीएनयू को ऑन-बोर्ड किया गया है। 14.02.2023 तक, देश भर में पायलट के तहत लगभग 153990 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। समिति का मत है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलने में मदद मिलेगी। समिति को अवगत कराया गया कि भारतनेट में बेहतर तालमेल के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में विलय कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि इस योजना पर प्रतिक्रिया उत्साहजनक है, तथापि, समिति की सुविचारित राय है कि इसकी सफलता निरंतर निगरानी पर निर्भर करेगी। चूंकि, इस योजना को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया गया है, इसलिए समिति चाहेगी कि विभाग समय-समय पर योजना की प्रभावकारिता का आकलन करे ताकि संभावित कमियों को दूर किया जा सके और पूर्ण पैमाने पर लागू करने से पहले और सुधार लाया जा सके। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

यूएसओएफ के अंतर्गत प्रक्रियाधीन कार्यकलापों के कार्यान्वयन की स्थिति:

10. यूएसओएफ के तहत विभाग ने देश के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और ओएफसी जैसी अवसंरचनाओं के

निर्माण तक पहुंच प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। विभाग की कई प्राथमिकता प्राप्त योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, कोच्चि से लक्षद्वीप तक पनडुब्बी केबल बिछाने सहित द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मोबाइल कनेक्टिविटी, हिमालयी राज्यों, पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों के कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवाओं के लिए योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं के लिए योजना और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाएं के लिए योजना आदि शामिल हैं। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, प्रक्रियाधीन कार्यकलापों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

क. उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी):-

सीटीडीपी के अंतर्गत उत्तर-पूर्व क्षेत्र के न जुड़े गांवों को कवर करने के लिए 3 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मेघालय के कवर न किए गए गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने और राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ निर्बाध कवरेज प्रदान करने के लिए, यह कार्य मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड को सौंपा गया है। कार्यक्रम के अंतर्गत संशोधित लक्ष्य में 758 गांवों और 11 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलों का प्रावधान है और इनमें से क्रमशः 480 गांवों और 2 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलों को कवर किया गया है। समिति ने यह नोट करती है कि मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड के दायरे में अतिरिक्त 723 गांवों को जोड़ा गया है, जिसके लिए 18 महीने की अतिरिक्त रोल-आउट अवधि प्रदान की गई है। इस प्रकार, अंतिम संशोधित दायरे के अंतर्गत मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड को 24.05.2024 तक 1481 गांवों और 9 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थलों को कवर करने वाले 1094 स्थल का कार्य सौंपा गया है। समिति विभाग से यह सिफारिश करती है कि वे चालू परियोजना की

उचित और कड़ी निगरानी करे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करे।

आगे, समिति नोट करती है कि अरुणाचल प्रदेश के 1683 कवर न किए गए गांवों और असम के 2 जिलों (691 गांवों) में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और असम में सेवाओं के प्रावधान के लिए मैसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और मेसर्स रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के साथ 1255.49 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 1683 गांवों में से, अरुणाचल प्रदेश के केवल 97 गांव और असम के 691 गांवों में से 2 जिलों के केवल 122 गांवों को अब तक कवर किया गया है। इसलिए, समिति स्पष्ट रूप से दूरसंचार विभाग से स्थिति की नियमित रूप से जांच करने और चालू परियोजनाओं का निर्धारित समय में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है। विभाग को परियोजनाओं के कार्यान्वयन की लगातार निगरानी करनी चाहिए और उनके चालू होने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। समिति विभाग से सख्त निर्देशों और पर्यवेक्षण के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी आग्रह करती है। समिति उठाए गए कदमों और उसके परिणामों से भी अवगत होना चाहेगी।

ख. आकांक्षी जिलों के 502 गांव (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार): -

समिति नोट करती है कि कि चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 112 आकांक्षी जिलों में 502 कवर न किए गए गांवों के लिए 421.65 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत वाली योजना को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

राज्यों के लिए मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, राजस्थान के लिए मेसर्स भारती हेक्साकॉम लिमिटेड और बिहार के लिए मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को 2021 में काम दिया गया है। समिति नोट करती है कि 462 मोबाइल टावरों की स्थापना करके 529 गांवों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में अब तक इन राज्यों में 119 मोबाइल टावरों को स्थापित करके केवल 146 गांवों को कवर किया गया है। अतः समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि जारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए। परियोजना का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समयबद्ध समय सीमा निर्धारित की जाए और कंपनियों द्वारा उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। इस संबंध में, विभाग से अनुरोध है कि वह तत्काल आधार पर स्थिति का जायजा ले और इस संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी जानकारी प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करे।

ग. आकांक्षी जिलें के शेष 7,287 गांव (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा):

समिति नोट करती है कि इस परियोजना में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 कवर न किए गए गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं का प्रावधान शामिल है। 3765.47 करोड़ रुपये की लागत से 3 राज्यों के लिए मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और 2 राज्यों के लिए मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ 20.05.2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना को नवंबर, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अभी तक केवल सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। समझौते के अनुसार, 4779 मोबाइल टावर स्थापित करके 7287 गांवों को

कवर किया जाना था। परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और मैसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड को सौंपी गई परियोजनाएं समय-सीमा के भीतर पूरी की जाएं और प्रभावी निष्पादन के लिए इनकी बारीकी से निगरानी की जाए। समिति यह भी चाहती है कि इस संबंध में उठाए गए कदमों और होने वाली प्रगति से उसे अवगत कराया जाए।

वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संचार सेवाओं के लिए योजना

11. समिति नोट करती है कि भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा 10 प्रभावित राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 106 जिलों में 2343 2जी टावरों की स्थापना करके एलडब्ल्यूई चरण-I को कार्यान्वित किया गया था। यह परियोजना बीएसएनएल को सौंपी गई है क्योंकि ये साइटें बीएसएनएल की हैं। 2426 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मौजूदा 2जी एलडब्ल्यूई चरण-I स्थलों के 4जी उन्नयन और विस्तार प्रचालनात्मक और रखरखाव को अनुमोदित किया गया है। तथापि, समझौते पर हस्ताक्षर अभी विचाराधीन है। समिति यह भी नोट करती है कि मंत्रिमंडल ने 23.05.2018 को एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना को मंजूरी दे दी थी। एलडब्ल्यूई चरण-II के तहत 2542 4जी टावर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और भारती एयरटेल लिमिटेड के साथ 2211.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना को मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समिति आगे यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य 2000 टावरों की स्थापना का था, जिसमें से केवल 284 टावर स्थापित किए गए

हैं। समिति विभाग से आग्रह करती है कि वह इस बाधा को दूर करने के तरीकों और साधनों के बारे में सोचे ।

समिति महसूस करती है कि इन क्षेत्रों में 4जी सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान से विभिन्न सेवाओं को लोगों के द्वार तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी और परियोजना के क्रियान्वयन में और देरी से इन क्षेत्रों में लोगों की कनेक्टिविटी की समस्या और बढ़ेगी। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि परियोजना निर्धारित समय के अनुसार यानी मार्च 2023 को पूरी हो जाएगी। समिति विभाग से आग्रह करती है कि सभी संभावित परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाओं के लिए यथार्थवादी समय-सीमा तय करें और निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाएं कि एलडब्ल्यूई चरण-II परियोजना बिना किसी और विलंब के पूरी हो। समिति यह भी सिफारिश करती है कि एलडब्ल्यूई चरण-I के अंतर्गत 2343 2जी टावरों को 4जी में स्तरोन्नत करने की योजना, जो विचाराधीन है, को भी यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। समिति को योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रगति और लक्ष्यों के बारे में सूचित किया जाए।

रक्षा स्पेक्ट्रम : रक्षा सेवाओं के लिए ओएफएसी आधारित नेटवर्क

12. समिति नोट करती है कि रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी नेटवर्क एक अति महत्वपूर्ण योजना है जिसका क्रियान्वयन बीएसएनएल द्वारा दूरसंचार विभाग की तरफ से किया जा रहा है। यह सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना है जिसका क्रियान्वयन रक्षा त्रि-सेवाओं के लिए टर्नकी आधार पर किया जा रहा है। परियोजना में संपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान हैं जिसमें ऑप्टिकल फाइबर

केबल (ओएफसी), पारेषण उपकरण, माइक्रोवेव, सैटेलाइट इंक्रिप्टर, एंड-प्वाइंट इक्विपमेंट, डाटा सेंटर आदि जैसे विभिन्न नेटवर्क घटक शामिल हैं। समिति विभाग के इस निवेदन को स्वीकार करती हैं कि यह एक अत्यंत ही जटिल परियोजना है और इसमें कुछ बहुत ही कठिन क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना शामिल है। तथापि समिति यह जानकर प्रसन्न है कि बाधाओं के बावजूद 60000 किलोमीटर में से लगभग 58740 किलोमीटर अर्थात 97.9 प्रतिशत ओएफसी केबल बिछा दिया गया है। साक्ष्य के दौरान दूरसंचार विभाग के सचिव इस वर्ष के अंत तक परियोजना के समाप्त हो जाने के बारे में आशान्वित थे। समिति को विश्वास है कि जैसा कि विभाग ने आश्वासन दिया है, रक्षा सेवाओं के लिए ओएससी नेटवर्क 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। समिति चाहती है कि इस संबंध में गंभीर प्रयास किए जाएं और आशा करती है कि विभाग/बीएसएनएल साक्ष्य के दौरान समिति को दिए गए आश्वासन पूरा करेगी। इस संबंध में यह स्मरण रखा जाए कि परियोजना अपने अंतिम चरण में है और वर्ष 2023-24 के लिए 2158 करोड़ रुपये की शेष राशि की मांग की गई है जिसे बजट अनुमान 2023-24 के अंतर्गत आवंटित कर दिया गया है। इसलिए, समिति विभाग/बीएसएनएल पर जोर देती है कि वह परियोजना के अंतर्गत नियत बजटीय आवंटन का उपयोग सुनिश्चित करें। समिति इस संबंध में विभाग द्वारा की गई पहलों और हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-डब्ल्यू ए एन आई)

13. विभाग ने समिति के समक्ष बताया कि देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार में गति लाने के लिए सरकार ने 9 दिसंबर, 2020 को पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स (पीडीओए) और पब्लिक डाटा

ऑफिसेज (पीडीओ) द्वारा सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना करने का अनुमोदन कर दिया है। साक्ष्य के दौरान यह सूचित किया गया कि कुल 152 पीडीओ और 144816 पीएम-डब्ल्यूएनआई यूनिट्स कार्य कर रहे हैं। योजना उन ग्रे स्पॉट्स में कार्य करेगी जहां कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, जैसे मॉल के अंदर, एयरपोर्ट, बस स्टैंड पर, सरकारी अस्पतालों आदि में। समिति डिजिटल इंडिया और पूरे भारतवर्ष में एक सुदृढ़ डिजिटल संचार अवसंरचना बनाने की दिशा में इसे सराहनीय कदम मानती है। यह प्रौद्योगिकी उद्यमियों को वाईफाई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का विकास करने और उसे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी जिससे मेक इन इंडिया योजना को भी बढ़ावा मिलेगा। उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए यह नई पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम पीडीओ के रूप में दुकानदारों के लिए नई व्यवसाय मॉडल को भी सक्षम बनाएगी जिससे आय, रोजगार, जीवन की गुणवत्ता, व्यवसाय करने में आसानी, आदि को बढ़ावा मिलेगा। योजना की महत्ता को देखते हुए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों को और मजबूत बनाए जाने की जरूरत है ताकि आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा दिया जा सके और देश में काफी संख्या में नौकरियां पैदा की जा सकें। इसलिए, समिति विभाग पर इस बात के लिए जोर देती है कि वह कनेक्टिविटी की कमियों की पहचान करने के लिए अपने प्रयासों में और तेजी लाएं तथा प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें। इसके साथ ही, समिति इस बात पर जोर देना चाहेगी कि विभाग द्वारा आवधिक निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए ताकि योजना का उचित क्रियान्वयन हो सके। समिति इस संबंध में किए गए कार्य से अवगत होना चाहिए

यूनिवर्सल चार्जिंग डिवाइस पर नीति अपनाने की जरूरत

14. समिति की चर्चा के दौरान एक सतत मुद्दा जो सामने आया है, वह सभी प्रकार के मोबाइल फोनों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग डिवाइस से संबंधित था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूनिवर्सल चार्जर से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार चार्जर के कारण होने वाली असुविधा में कमी लाने में सहायता मिलेगी और इसके साथ ही ई-कचरा में कमी में भी सहायता मिलेगी। इस विचार को बढ़ाते हुए यह सूचित किया गया कि आईटीयू-टी ने सुझाव जारी किया है जिसमें मोबाइल फोनों के लिए यूनिवर्सल चार्जर का सुझाव दिया गया है लेकिन इसके लिए भारत में अभी अधिदेश दिया जाना है। समिति का सुविचारित मत है की इस स्थिति को यूरोपीय राष्ट्रों में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार, यह भारत के लिए अवसर की बात है कि वह इसका अनुपालन करने के लिए संपूर्ण विश्व के लिए उदाहरण बने। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय उपाय करने की अति आवश्यकता है कि भारत आईटीयू-टी के सिफारिशों की तर्ज पर बेहतर वैश्विक प्रणालियां अपनाने में पीछे नहीं है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने समिति को जानकारी दी कि उपभोक्ता कार्य मंत्रालय इस विषय पर एमईआईटीवाई और उद्योगों के साथ कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त, ट्राई ने हरित संचार पर एक परामर्श पत्र जारी किया है जिसमें इस मामले को भी शामिल किया गया है और इस विषय पर सिफारिशें देगी। अब जबकि ट्राई की सिफारिशें आनी है, समिति पब्लिक डोमेन में सिफारिश आने तक अपनी टिप्पणियां नहीं देगी। तथापि इस अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति आईटीयू-टी के सिफारिश के अनुसार वैश्विक पहल के साथ भारतीय प्रथा में संगति लाने के लिए दूरसंचार विभाग को एमईआईटीवाई के साथ मिलकर विवेकपूर्ण उपाय करने के लिए कहती है। समिति प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने की 3 माह के अंदर इस मामले में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

पीएसयू के कार्यक्रम की समीक्षा

भारत संचार निगम लिमिटेड : इसकी 4जी सेवाएं शुरू करने के लिए रोडमैप

15. समिति नोट करती है कि सरकार ने बीएसएनएल में स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकसित करने और लगाने का निर्णय लिया है। समिति इस दिशा में किए गए प्रयासों की सराहना करती है। समिति नोट करती है कि सरकार ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ का पैकेज दिया है और बीएसएनएल एबिटडा सकारात्मक हो गया है। समिति के विचार में वर्तमान में दूरसंचार व्यवसाय मोबाइल डाटा और इंटरनेट स्पीड द्वारा चालित है और बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवाएं शुरू करने में विलंब के परिणामस्वरूप डाटा और स्पीड दोनों का उपयोग नहीं हो रहा है। दूरसंचार विभाग के सचिव इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बहुत ही ईमानदार थे कि दूरसंचार कंपनियों की सफलता की कुंजी डाटा है। विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार बीएसएनएल/एमटीएनएल निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल डाटा का 1 प्रतिशत से भी कम का उपयोग करते हैं। ये उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि बीएसएनएल/एमटीएनएल तीव्र गति से अपने सब्सक्राइबर आधार को खो रही है इसलिए विभाग/बीएसएनएल को युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। विभाग के साक्ष्य के अनुसार कंपनी को 2026-27 तक शुद्ध लाभ होने की आकांक्षा है। इसलिए समिति, विभाग से आग्रह करती है कि वह बीएसएनएल की उपकरण खरीद प्रक्रिया में गति लाए जिसके लिए निविदा पहले ही जारी कर दी गई है और इसमें ओर विलंब किए बिना बीएसएनएल की 4जी सेवाएं शुरू करने में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करें ताकि इसकी सही सक्षमता का दोहन किया जा सके। समिति को यह भी आशा है कि बीएसएनएल को समयबद्ध तरीके से अपनी

सेवाएं शुरू करने की अपेक्षाओं के अनुसार 4जी स्पैक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। यह सराहनीय होगा यदि इच्छित कार्य यथाशीघ्र किया जाए।

बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

16. समिति इस तथ्य से पूरी तरह अवगत है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास भवनों सहित बड़ी संख्या में भूमि संपत्तियां हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के लिए भूमि/भवन और टावर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण एक घटक है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएसएनएल में मुद्रीकरण के लिए पहचाने गए भूमि/भवन परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 67000 करोड़ रुपए है। वर्तमान वर्ष के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के मुद्रीकरण के लिए क्रमशः 20000 करोड़ रुपए और 18000 करोड़ रुपए के मूल्य के कुल 70 भूमि और भवन संपत्तियों की पहचान की गई है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास महत्वपूर्ण और गैर-महत्वपूर्ण दो प्रकार की परिसंपत्तियों हैं। गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में भूखंड और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों में फाइबर और टावर हैं। चर्चा के दौरान समिति को सूचित किया गया कि बीएसएनएल निर्मित भवनों में सभी खाली जगहों का किराए के लिए पहले से ही उपयोग कर रहा है और पिछले वर्ष बीएसएनएल को किराए से 212 करोड़ रुपए की आय अर्जित हुई है और यह आय इस वर्ष 260 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। इसी तरह एमटीएनएल में किराए से लगभग 350 करोड़ रुपए की आय हुई है और उन्होंने लगभग 200 करोड़ की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण किया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि भूतकाल में किए गए सशर्त समनुदेशन और राज्य सरकारों या स्थानीय निकायों से अनुमति लेने की आवश्यकता के कारण अन्य संपत्तियों में चुनौतियां/बाधाएं हैं जिसके लिए विभाग बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ मामले पर चर्चा कर

रही है। एमटीएनएल के संबंध में समिति नोट करती है कि मुंबई में अधिकांश परिसंपत्तियों के रिजर्वेशन/डेजिग्नेशन संबंधी मुद्दे हैं और ये इन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की संभावनाओं को बाधित कर रहे हैं। एमटीएनएल इन परिसंपत्तियों के रिजर्वेशन/डेजिग्नेशन को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के समक्ष मामले को उठा रही है। समिति का सुविचारित मत है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास भारी संख्या में महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण परिसंपत्ति हैं जिनके उचित मुद्रीकरण से उन्हें भारी राजस्व अर्जित हो सकता है जिनके उपयोग से न केवल उनका पुनरुद्धार हो सकता है वरन सतत राजस्व स्रोत को बनाए रखने के लिए भी उपयोग हो सकता है। समिति यह भी महसूस करती है कि परिसंपत्तियों का बही-मूल्य अच्छी तरह से नहीं दर्शाया जाता है और यदि परिसंपत्तियों के बही-मूल्य को वर्तमान मूल्य के आधार पर दर्शाया जाए तो बीएसएनएल/एमटीएनएल की वर्तमान में होने वाली अधिकांश वित्तीय समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसके उपरांत परिसंपत्तियों का सफल मुद्रीकरण से सरकारी राजस्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर बोझ डाले बिना दोनों कंपनियों के पुनरुद्धार प्रक्रिया के उद्देश्य में सहायता मिलेगी। समिति नोट करती है कि विभाग/बीएसएनएल के परिसंपत्तियों के सौहार्दपूर्ण समाधान और सफल मुद्रीकरण के लिए संबंधित राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के साथ रिजर्वेशन और डेजिग्नेशन संबंधी मुद्दे उठाए हैं। समिति का सुविचारित मत है कि अप्रयुक्त पड़ी इन परिसंपत्तियों के लाभप्रद उपयोग बीएसएनएल/एमटीएनएल और संबंधित राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों दोनों के बृहत हित में होगा। इसलिए इस मामले को उपयुक्त स्तर पर राज्य सरकारों के साथ ईमानदारी पूर्वक उठाए जाए और इसे तार्किक परिणीति पर पहुंचाया जाए। समिति को परिसंपत्तियों के नीलामी, जो की जा सकती है, से होने वाली आय सहित इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए। समिति इस सिफारिश के अनुसरण में किए गए उपायों से भी यथाशीघ्र सूचित होना चाहेगी।

बीएसएनएल/एमटीएनएल के लिए पूंजी निवेश

17. समिति नोट करती है कि 2023-24 के दौरान विभिन्न पुनरुद्धार उपायों को क्रियान्वित करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 52937 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समिति को चर्चा के दौरान सूचित किया गया कि 4जी सेवाएं नहीं होने के बावजूद भी बीएसएनएल पिछले 4 वर्षों से अपनी आय बनाए रखने में सक्षम रहा है। पिछले वर्ष से आय में 14% अर्थात् 1600 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। सतत निगरानी रखने से कंपनी प्रचलनात्मक व्यय पर अंकुश लगा सकी है। वीआरएस के बाद कंपनी को होने वाले कर्मचारी लागत में बचत और ओपेक्स में बचत होने से बीएसएनएल लगभग 3 वर्षों से सकारात्मक ईबीआईटीडीए प्राप्त करने में सक्षम रहा है। यद्यपि बीएसएनएल के लिए 4G अभी शुरू की जानी है तथापि समिति नोट करती है कि कंपनी अन्य स्रोतों से राजस्व अर्जित करने के लिए कठिन प्रयास कर रही है। इस वर्ष किराए से 260 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व आय होने का अनुमान है। बीएसएनएल की योजना है कि वह साझेदारी पर और ज्यादा टावर बढ़ा कर अधिक आय अर्जित करें। अधिशेष निर्मित जगह को पट्टे पर देकर परिसंपत्तियों के पुनरुपयोग से जनवरी 2023 तक कुल 202 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ है। समिति को सूचित किया गया है कि एफटीटीएच आधारित फाइबर कनेक्शन प्रगति पर है और यह बीएसएनएल की सफलता की कहानी है। यह बताया गया कि पिछले वर्ष एफटीटीएच से राजस्व में वृद्धि 1119 करोड़ रुपए से बढ़कर 1506 करोड़ रुपए हो गयी है। समिति नोट करती है कि वीआरएस के क्रियान्वयन से बीएसएनएल के वेतन व्यय में काफी कमी आई है तथापि आने वाले वर्षों में बीएसएल के अनुमानित घाटे को कम करने के लिए और ज्यादा प्रयास किए जाने की जरूरत है समिति को आशा है कि स्पेक्ट्रम के आवंटन और 2023-24 में 4जी सेवाओं के शुरू होने और कैपेक्स

सहायता से आने वाले वर्षों में राजस्व में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कंपनी के नेटवर्क के विस्तार में सहायता मिलेगी जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं की उच्चतर उपलब्धता और राजस्व में वृद्धि होगी। ये पहल बीएसएनएल के लाभ में वृद्धि करने में सहायता करेगी, ऐसी आशा करते हुए समिति सिफारिश करती है कि विभाग/बीएसएनएल अपने राजस्व अर्जन की संभावना का पूरी तरह से दोहन करने के लिए सतत प्रयास करते रहे। समिति बीएसएनएल से आशा करती है कि वह उपभोक्ताओं की निरंतर बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने ऑफर में विविधता लाए। समिति संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

18. समिति नोट करती है कि वर्ष 2023-24 के लिए एमटीएनएल का अनुमानित राजस्व और व्यय क्रमशः 17500 करोड़ और 4970.78 करोड़ रुपए है। तथापि 2023 में 1810 करोड़ रुपए की आय के लक्ष्य की तुलना में एमटीएनएल केवल 775.89 करोड़ रुपए प्राप्त करने में सक्षम रहा। विभाग ने समिति को सूचित किया कि लक्ष्य प्राप्त नहीं करने के मुख्य कारणों में सीमित बाजार क्षेत्र, अति संतृप्त बाजार, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, तीव्र गति से प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आदि जैसे कारण रहे हैं। समिति एमटीएनएल की कठिन परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत है। 31 जनवरी, 2023 के अनुसार एमटीएनएल का कुल बकाया ऋण 28581 करोड़ रुपए है। समिति को सूचित किया गया है कि एमटीएनएल के अरक्षणीय कर्ज को देखते हुए परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, ए जी आर देय राशि, ऋण समाधान, एमटीएनएल का बीएसएनएल के साथ विलय संबंधी आगे की कार्रवाई जैसे मामले सचिवों की समिति के समक्ष उठाए जाने चाहिए जिसमें व्यय सचिव, दूरसंचार सचिव, डीआईपीएएम सचिव और लोक उद्यम विभाग के सचिव

शामिल हैं जो दूरसंचार पीएसीयू की संरचना और प्रचलनात्मक एकीकरण के तरीके सुझाएगी। इस संबंध में बीएसएनएल ने एक ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किया है। उसने पहले ही अपने रिपोर्ट में विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत की है, जिसकी जांच की जा रही है। समिति सिफारिश करती है कि और विलंब किए बिना बीएसएनएल और एमटीएनएल की वर्तमान विलय की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु प्रयासों में गति लाई जाए समिति इस संबंध में उठाए गए कदमों और इसके परिणामों से अवगत होना चाहेगी।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड

19. समिति नोट करती है कि 2021-22 के दौरान आईटीआई की कुल आय 2115 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 121 करोड़ रुपए था। तथापि 2022-23 के दौरान 30 सितंबर, 2022 तक आईटीआई का कुल शुद्ध घाटा 200 करोड़ रुपए रहा। समिति को सूचित किया गया कि 2022-23 के दौरान आईटीआई के शुद्ध घाटे प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कलपुर्जों और चिप की कमी तथा स्वदेशी 4जी प्रौद्योगिकी के प्रूफ-ऑफ-कांसेप्ट (पीओसी) में विलंब, बीएसएनएल द्वारा क्रय आदेश देने में विलंब था। समिति नोट करती है कि 2022-23 के दौरान 9 माह में व्यय का वार्षिक मूल्य 596 करोड़ रुपए और कुल आय 396 करोड़ रुपए था। इसलिए आईटीआई को इस वर्ष घाटा होने का अनुमान है। तथापि, आईटीआई को आशा है कि वह वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक राजस्व लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और उपलब्ध आदेशों को अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्व-निर्मित उत्पादों का परियोजना की जरूरतों के लिए उपयोग किया जा रहा है जिससे उन्हें अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो रहा है। समिति को सूचित किया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआई की अनुमानित आय और व्यय क्रमशः 2972 करोड़

और 2853 करोड़ रुपए होगी और इस प्रकार अनुमानित शुभ लाभ 119 करोड़ रुपए होगी। पूंजीगत व्यय के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2022-23 में 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान चरण में घटाकर 187.82 करोड़ रुपए कर दिया गया और दिसंबर, 2022 तक संशोधित अनुमान का वास्तविक उपयोग लगभग 42.7% है। समिति को सूचित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले दो तिमाही में उपलब्धि कम रही और आईटीआई को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक कार्य निष्पादन में सुधार करने की आशा है। वर्ष 2023-24 के लिए 220 करोड़ रुपए के प्रस्तावित राशि की तुलना में आईटीआई पुनरुद्धार (साम्य निवेश) के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 160 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समिति का सुविचारित मत है कि विगत वर्ष में अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए आईटीआई लिमिटेड को एएससीओएन IV परियोजना, भारत नेट चरण दो परियोजनाओं और सौर पैनल, एचडीपीई डक्ट, ओएफएसी जैसे स्वनिर्मित वस्तुओं में लाभप्रद मार्जिन के तर्ज पर अपनी चालू परियोजनाओं को लाभप्रद मार्जिन के आधार पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, कंपनी "नए उत्पाद (मल्टी पोस्ट ई-वोटिंग मशीन) और आगामी परियोजना 4जी विनिर्माण" में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए, समिति को आशा है कि यदि आईटीआई लिमिटेड के विनिर्माण क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जाए तो आईटीआई लिमिटेड अपना कायाकल्प कर सकती है और आने वाले वर्षों में राजस्व आय भी बढ़ा सकती है। समिति को यह भी आशा है कि वर्ष 2023-24 में आवंटित किए गए धन का पूरा उपयोग करने के ईमानदार प्रयास किए जाएंगे और यदि जरूरत हो, तो संशोधित चरण में और ज्यादा धन की मांग की जा सकती है। समिति को आशा है कि विभाग सभी संभव सहायता करेगी और आईटीआई आवंटित धनराशि का इष्टतम

उपयोग करने में सक्षम होगी। समिति इस संबंध में की-गई-कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज (आईटीआई) लिमिटेड : इसके पुनरुद्धार संबंधी योजना और आगे की कार्रवाई

20. जांच के दौरान समिति को सूचित किया गया कि 05.04.2021 को हुई अपनी बैठक में नीति आयोग ने सिफारिश की थी कि आईटीआई लिमिटेड का कार्यनीतिक विनिवेश किया जाए। इसके उपरांत, विनिवेश संबंधी सचिवों की कोर समूह की बैठक 24 जून, 2021 को हुई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई कि आईटीआई लिमिटेड को अपने क्षेत्र में न्यूनतम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में नहीं बनाए रखा जा सकता और आईटीआई लिमिटेड को इसकी भूमि के अविलयन के पश्चात कार्यनितिक विनिवेश के लिए लिया जाए। इसके बाद, दूरसंचार विभाग ने सहमति दी है और डीआईपीएएम को वैकल्पिक तंत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। वर्तमान में यह मामला डीआईपीएएम के विचाराधीन है।

समिति यह भी नोट करती है कि आईटीआई लिमिटेड के स्वामित्व वाले अचल परिसंपत्तियों भूमि/भवनों का मुद्रिकरण आईटीआई लिमिटेड के पुनरुद्धार के प्रमुख घटकों में से एक हो सकता है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आईटीआई लिमिटेड के स्वामित्व वाले अचल परिसंपत्तियों भूमि/भवनों का कुल क्षेत्रफल 1390.337 एकड़ है। समिति का दृढ़ मत है कि परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण के उचित कार्यान्वयन से उसे भारी राजस्व अर्जित हो सकता है जिसका उपयोग न केवल इसके पुनरुद्धार के लिए किया जा सकता है, वरण इसके साथ ही सतत राजस्व के स्रोत को बनाए रखने में भी हो सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कंपनियों के ऐसी विशाल परिसंपत्तियों का सर्वोत्तम उत्पादकता उपयोग के तरीके के लिए एक समुचित अध्ययन कराया जाए। समिति विभाग से यह भी आग्रह करती है कि विनिवेश से बचने के लिए वह आईटीआई के साथ बेहतर संबंध रखने वाले किसी मौजूदा पीएसयू के साथ इसके विलय की संभावना पर विचार करें। समिति इस सिफारिश के अनुसरण में किए गए उपायों से यथाशीघ्र अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली;

17 मार्च, 2023

26 फाल्गुन, 1944 (शक)

प्रतापराव जाधव,

सभापति,

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी स्थायी समिति।